● वर्ष-3
● अंक-185
रायपुर, मंगलवार
12 मार्च 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› कलरिंग से डैमेज हो रहे हैं बाल....

ग्राम पंचायतों को 9 थीम पर किया गया सम्मानित

सरपंच गांव के विकास की चाबी- पाटिल

पंचायत प्रतिनिधियों के सुझाव पर चलेगा पंचायत विभाग- उपमुख्यमंत्री

रायपुर। सरपंच गांव के विकास की चाबी हैं। ग्रामीणों ने बड़ी उम्मीद से भरोसा कर गांव के विकास की चाबी सरपंचों को सौंपी है। छत्तीसगढ़ सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यधारा में शामिल कर प्रोत्साहित कर रही है। यह बात राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायतीराज कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कही। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, विधायक अनुज शर्मा ने भी राज्य स्तरीय महापंचायत को संबोधित किया। राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों, ज्ञानोदय वाचनालय एवं अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर प्रदाय हेतु राशि अंतरण किया गया। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विशिष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को 9 थीम पर, नियद नेल्लानार के परिकल्पना को

साकार करने वाले ग्राम पंचायतों के सरपंचों, लखपति दीदी तथा ड्रोन दीदी को सम्मानित किया गया।

केन्द्रीय पंचायतीराज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में गांवों का विकास पीछे नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान और जोर गांवों के विकास पर है। विकसित भारत यात्रा के दौरान सरकार की योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाकर लोगों को लाभान्वित किया गया है।

राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटी के अंतर्गत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के अंतर्गत सत्ता की सबसे मूल इकाई पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक सुझाव और सहयोग प्राप्त करने के आकांक्षा के साथ इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विस्तार से सरकार द्वारा पंचायत विभाग में लिये गये निर्णयों की जानकारी दी।

9 थीम पर किया गया सम्मानित

थीम-1 अंतर्गत गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत नागम, जनपद पंचायत लुण्ड्रा,

थीम 2- के अंतर्गत स्वस्थ ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत सांकरा जनपद पंचायत नगरी, जिला-धमतरी

थीम-3- ग्राम पंचायत निलजा, जनपद पंचायत-धरसींवा, जिला-रायपुर को

थीम 4- ग्राम पंचायत बाघनदी, जनपद पंचायत डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को थीम-04 जल की प्रचुरता ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित

थीम 5- ग्राम पंचायत है जोंकबाला, जनपद पंचायत-कुनकुरी, जिला - जशपुर को स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित किया जाता है।

थीम 6- ग्राम पंचायत आड़ावाल, जनपद पंचायत- जगदलपुर, जिला-बस्तर, ने बुनियादी ढांचे को शहर जैसा विकसित करने का प्रयास पर

थीम 7- ग्राम पंचायत पिकरीपारा, जनपद पंचायत- गुरुर, जिला बालोद, समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए आगे बढ़ रही है। अतः ग्राम पंचायत को

थीम 8 - सुशासन में ग्राम पंचायत के समस्त नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करना एवं पारदर्शिता, जवाबदेही, सहानुभूतिपूर्ण उत्तरदायित्व एवं नागरिकों का अधिकतम सहयोग, भागीदारी

थीम 9- ग्राम पंचायत खडगवांकला, जनपद पंचायत-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर को सुशासन के दृष्टिकोण को चरितार्थ करते हुए अपने ग्राम पंचायतों को समस्त उत्तरदायित्व के निर्वहन में सक्षम बनाने हेतु सुशासन का उदहारण प्रस्तुत किया है।

3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता

सीएए को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में हो सकता है। बीजेपी ने इस बार अबकी बार 400 पार का नारा दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से ये बात कह चुके हैं कि अगर 400 पार करना है तो किस तरह से काम करना है।

जनता के बीच जाकर पीएम मोदी की तरफ से घोषणाएं की जा रही हैं। वहीं इसी क्रम में आज सीएए की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तीन देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई इसमें शामिल हैं। इसमें मुसलमानों को इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये तीनों मुस्लिल बहुल देश हैं और वहां अल्पसंख्यक अन्य धर्मों के लोग हैं।

भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले। ऐसे शर्णार्थियों को नागरिकता प्रधान की जा सके। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए नियमों को अधिसूचित किए जाने से संबंधित खबरों पर कहा कि लोगों के साथ भेदभाव करने वाली किसी भी चीज का विरोध करेंगे। एनआरसी और सीएए के नाम पर लोगों को 'डिटेंशन कैंप' में भेजा जाएगा, तो विरोध करूंगी। ममता ने कहा कि सीएए और एनआरसी बंगाल और पूर्वोत्तर के लिए संवेदनशील मुद्दा, लोकसभा चुनाव से पहले अशांति नहीं चाहती।

अमित शाह पहले ही कर चुके साफ - अमित शाह ने कहा था कि 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे हैं। जिनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए और आज हमारी नागरिकता नहीं है। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे। सिटिजनशिप अमेडमेंट एक्ट को पहले ही कैबिनेट में लागूकर सभी को नागरिकता दी जाएगी। अमित शाह ने एक चुनावी सभा में भी कहा था कि सीएए के खिलाफ हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए केवल उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है।

विराट और विशाल फैसले- पीएम मोदी ने कहा था कि विराट और विशाल फैसले के लिए मैं जाना जाता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि वो इसे लेने से हिचकते भी नहीं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी मुझे अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। मैं छोटा नहीं सोच सकता, न ही मैं छोटे सपने देखता हूं, न ही मैं छोटे संकल्प लेता हूं।

मैं जो भी चाहता हूं, वह बड़ा चाहता हूं। मुझे जो चाहिए विराट चाहिए, विशाल चाहिए और तेज गति से चाहिए।यानी प्रधानमंत्री ने संकेत सुबह ही दे दिए गए थे। पीएम मोदी ने हर बार अपने फैसले से चौंकाया है। देश की जनता के हितों को प्रभावित भी करता है। उससे आम आदमी पूरी तरह से जुड़ा हुआ होता है।

विपक्ष का केंद्र सरकार पर हमला

वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने का केंद्र का निर्णय चुनावों का ध्रुवीकरण करने के लिए बनाया गया है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीक़े से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफ़ेद झूठ की एक और झलक है। रमेश ने कहा कि नियमों की अधिसूचना के लिए नौ बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में। यह इलेक्टोरल बांड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख़्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है।

साय सरकार की कृषक उन्नति योजना का आज केंद्रीय मंत्री मुंडा करेंगे शुभारंभ

करीब 25 लाख किसानों के बैंक खाते में 13 हजार 320 करोड़ किये जाएंगे ट्रांसफर

रायपुर। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कल 12 मार्च का दिन अविस्मरणीय रहेगा. इस दिन छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ जिला मुख्यालय बालोद स्थित सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में हजारों किसानों और ग्रामीणों की मौजूदगी में होगा. केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग 24 लाख 75 हजार किसानों को इस योजना के तहत 13 हजार 320 करोड़ रुपये की आदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किसानों से 3100 रूपये क्विंटल की दर से धान खरीदी की गारंटी दी थी. इस गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का प्रदेशव्यापी शुरूआत 12 मार्च मंगलवार को होने जा रहा है. इस योजना के तहत किसानों को आदान सहायता राशि का अंतरण उनके बैंक खातों में करने के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों सहित विकासखण्ड मुख्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे. कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 3100 रूपये प्रति क्विंटल धान के मूल्य के मान से अंतर की राशि प्रदान की जाएगी.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने दो आईटी कंपनियों मेसर्स स्क्वेयर बिजनेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद एवं मेसर्स रेडिकल माइंड्स टेक्नॉलाजिस प्राइवेट लिमिटेड को नवा रायपुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 90 हजार वर्गफीट बिल्ट-अप एरिया का आबंटन आदेश सौपा। ये कंपनियां आईटी इकाईयों की स्थापना तथा संचालन करेंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आईटी कंपनियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि नवा रायपुर को हम इनोवेशन हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं।

प्रमुख समाचार

संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इंकार

कोलकाता. ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों के हमले की जांच को सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में कोई दखल देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस और सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को हटा दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मामले को स्थानांतरित करने और मुख्य आरोपी शाहजहाँ शेख की हिरासत को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का निर्देश देने के बाद याचिका तत्काल दायर की गई थी। उच्च न्यायालय का निर्णय राज्य पुलिस के मामले को संभालने के तरीके और आरोपी शाहजहाँ शेख के कथित राजनीतिक प्रभाव पर चिंताओं पर आधारित था।

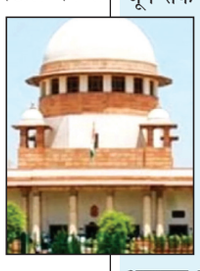

चुनावी बांडः सुको ने एसबीआई को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने को कहा है। याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और एसबीआई को कल तक सभी दस्तावेज जमा करने के कड़े निर्देश दिए। यह बहुत अच्छा फैसला है, मैं इसका स्वागत करती हूं। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसबीआई को 12 मार्च, 2024 को व्यावसायिक घंटों के अंत तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है। ईसी जानकारी संकलित करेगा और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च, 2024 शाम 5 बजे तक विवरण प्रकाशित करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 6 मार्च तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड खरीद के सभी विवरण प्रस्तुत करने और प्रक्रिया में देरी करने के अपने पिछले आदेश का पालन नहीं करने और प्रक्रिया में देरी करने के लिए एसबीआई को अवज्ञा के लिए भी फटकार लगाई।

साईबाबा को बरी करने के आदेश पर सुको का इंकार

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा और अन्य को माओवादियों से संबंध के मामले में बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध मानने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश ''प्रथम दृष्टया तर्कसंगत'' है। लेकिन, न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू के याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने के मौखिक अनुरोध को भी खारिज कर दिया और कहा कि इस पर उचित समय पर सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि यह बड़ी मुश्किल से बरी किए जाने का मामला है और सामान्य तौर पर, इस अदालत को यह अपील खारिज कर देनी चाहिए थी। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने पांच मार्च को साईबाबा (54) को बरी कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा। अदालत ने साईबाबा को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया था।

इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है चुनावी बॉण्ड

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी बॉण्ड का विवरण देने के लिए समय बढ़ाने संबंधी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की याचिका उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद सोमवार को दावा किया कि यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय बढ़ाए जाने का अनुरोध करने संबंधी एसबीआई की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने उसे 12 मार्च को कामकाजी घंटे समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग को उक्त विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग को भी एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने का निर्देश दिया। राहुल ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''नरेन्द्र मोदी के 'चंदे के धंधे' की पोल खुलने वाली है!

राहुल अपने दिमाग का संतुलन खो चुके हैंः आचार्य प्रमोद

नई दिल्ली। मोदी की गारंटी पर संदेह के लिए राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए, निष्कासित कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रविवार को कहा कि जो लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, वे निराधार बयान देने के लिए प्रवृत्त होते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी से बड़े पैमाने पर पलायन और दलबदल पर गहरा खेद व्यक्त किया, इसकी घटती किस्मत के लिए भगवान राम और सनातन मूल्यों जैसे प्रतिष्ठित लोगों के खिलाफ इसके कथित रुख को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस राम और सनातन के लोकाचार के बिल्कुल विपरीत इकाई बन गई है, यही कारण है कि वह अपने नेताओं और सदस्यों को प्रतिद्वंद्वी गुटों में खो रही है। राहुल के इस दावे पर कि पीएम मोदी की लगातार तीसरी बार वापसी का कोई आश्वासन नहीं है, निष्कासित कांग्रेस नेता ने एएनआई से कहा, देखिए, एक व्यक्ति, जो अपना दिमाग खो चुका है, कुछ भी कह सकता है। जैसा कि हमने बच्चों के साथ देखा है, वे अक्सर बिना कोई मतलब निकाले बातें करते रहते हैं। किसी बच्चे या नासमझ व्यक्ति की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय से मोदी सरकार को एक दिन में लगे दो झटके

नीरज कुमार दुबे

उच्चतम न्यायालय से मोदी सरकार को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक ही दिन में सर्वोच्च न्यायालय से मोदी सरकार को दो बड़े झटके लगे हैं। एक तो न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड मामले में डाटा देने के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली एसबीआई की याचिका खारिज कर दी। दूसरा न्यायालय उस याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें मांग की गयी है कि केंद्र सरकार को निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति नये कानून के तहत करने से रोका जाये। इस तरह अब एक तो चुनावी बॉण्ड योजना के तहत किसने किस पार्टी को कितना चंदा कब-कब दिया यह बात 15 मार्च तक उजागर हो जायेगी और साथ ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति नए निर्वाचन आयुक्तों के नामों को तय करने के लिए 15 मार्च को जो बैठक करने वाली है उस पर अब संशय के बादल मंडराने लगे हैं।

जहां तक चुनावी बॉण्ड योजना की बात है तो आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बॉण्ड संबंधी जानकारी का खुलासा करने के लिए समयसीमा बढ़ाए जाने का अनुरोध करने वाली भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की याचिका खारिज करते हुए उसे 12 मार्च को कामकाजी घंटे समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड संबंधी विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग को भी एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। हम आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय की इस पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने एसबीआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की दलीलों पर गौर किया कि विवरण एकत्र करने और उनका मिलान करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है क्योंकि जानकारी इसकी शाखाओं में दो अलग-अलग कक्षों में रखी गई थी। उन्होंने कहा कि अगर मिलान प्रक्रिया नहीं करनी हो तो एसबीआई तीन सप्ताह के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। पीठ ने कहा कि उसने एसबीआई को चंदा देने वालों और चंदा प्राप्त करने वालों के विवरण का अन्य जानकारी से मिलान करने का निर्देश नहीं दिया है। पीठ ने कहा कि एसबीआई को सिर्फ सीलबंद लिफाफा खोलना है, विवरण एकत्र करना है और निर्वाचन आयोग को जानकारी देनी है। पीठ ने बैंक से यह भी पूछा कि उसने शीर्ष अदालत के 15 फरवरी के फैसले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए हैं। पीठ ने कहा, ''पिछले 26 दिन में आपने क्या कदम उठाए हैं? आपकी अर्जी में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया।''

हम आपको याद दिला दें कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ''असंवैधानिक'' करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने अब एसबीआई की उस याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, पीठ ने एक अलग याचिका पर भी सुनवाई की जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है। उधर, अदालत के फैसले के बाद याचिकाकर्ता जया ठाकुर और वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है जोकि लोकतंत्र को मजबूत करेगा।

विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा- दूसरी ओर, अदालत के फैसले के बाद विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस ने चुनावी बॉण्ड का विवरण देने के लिए समय बढ़ाने की भारतीय स्टेट बैंक की मांग को हास्यास्पद करार देते हुए दावा किया कि सरकार को इस बात का डर है कि उसके सारे राज खुल जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि उच्चतम न्यायालय एक बार फिर से भारतीय लोकतंत्र को सरकार की साजिशों से बचाने के लिए सामने आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मामला बड़े भ्रष्टाचार का है तथा यह सरकार एवं उसके कॉरपोरेट मित्रों के बीच की सांठगांठ को भी उजागर करता है।

बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़, एक नक्सली ढेर

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच पीडिया के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक पुरुष नक्सली मारा गया है। पुलिस ने नक्सली का शव बरामद कर लिया है।

बीजापुर के पीडिया के जंगलों में सर्चिंग पर निकले बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ और सीआरपीएफ की टीम संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इस दौरान जवानों पर नक्सलियों ने अचानक फायरिंग कर दिया। जवानों ने भी नक्सलियों के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। जवानों का दावा है कि मुठभेड़ में कई नक्सली घायल हुए हैं। पुलिस पार्टी फिलहाल घटना स्थल की सर्चिंग कर रही है। जवानों ने भारी मात्रा नक्सली सामान बरामद किया है। बीजापुर एएसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस पार्टी वापस आने के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी।

पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में नक्सली गतिविधि बढ़ गई है। आज बीजापुर में एक युवक की नक्सलियों ने हत्या कर दी। नक्सलियों ने पहले युवक का दो दिन पहले अपहरण किया और फिर हत्या कर सड़क पर फेंक दिया। शव के पास भैरमगढ़ एरिया कमेटी का पर्चा मिला है। नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए हत्या करने की बात पर्चे में लिखी है।

इससे पहले 3 मार्च को कांकेर के छोटेबेठिया में

नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में बस्तर फाइटर का एक जवान शहीद हो गया। मुठभेड़ 10 लाख का इनामी नक्सली नागेश भी ढेर हुआ है। बीजापुर में ही 4 मार्च को पुलिस ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन नक्सलियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं।

बीजापुर में नक्सलियों ने पुलिस जवान के भाई का अपहरण कर हत्या की

बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में नक्सलियों की बर्बरता लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में दो बीजेपी नेताओं की हत्या करने वाले नक्सलियों ने एक युवक को पहले घर से उठा लिया फिर उसकी हत्या कर दी। घटना बीजापुर के कुटरू थाना क्षेत्र की है। शुक्रवार को नक्सलियों ने पेठा गांव के एक 35 साल के युवक का अपहरण कर लिया। युवक का नाम कुशु हेमला है। घर वालों ने युवक को ढूंढा लेकिन कहीं युवक का पता नहीं चल पाया। दो दिन बाद रविवार देर रात युवक का शव पाता कुटरु के पास सड़क पर मिला। घटना की पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना ने की है।

युवक कुटरू में रहता था। 8 मार्च को वह अपने गांव तेलीपेठा गया हुा था। जहां नक्सलियों ने उसका अपहरण किया और पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए उसकी हत्या कर दी। शव के पास से भैरमगढ़ एरिया कमेटी का पर्चा भी मिला है। जिसमें मुखबीरी का आरोप लगाते हुए हत्या करने के बारे में लिखा है।

मृत युवक के दोनों भाई पुलिस जवान है और बस्तर में ही अलग अलग जगह पदस्थ है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने युवक पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया और उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी।

मार्च के पहले हफ्ते में बीजापुर में नक्सलियों ने दो बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी थी। कोटमेटा इलाके से बीजेपी नेता कैलाश नाग का नक्सलियों ने पहले अपहरण किया फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इससे पहले नक्सलियों ने बीजेपी नेता तिरुपति कटला की शादी समारोह में धारदार हथियार से वार कर हत्या की थी।

पुलिस ने जिस महिला को बताया एक लाख की ईनामी, नक्सलियों ने दावे को बताया फर्जी

दो मार्च को पुलिस ने पामेड़ थाना क्षेत्र के जारपल्ली के जंगल से जिस एक लाख रुपये की ईनामी महिला नक्सली कट्टम रामबाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का प्रेसनोट जारी किया था। अब उस मामले को लेकर नक्सलियों की दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव गंगा ने प्रेसनोट जारी कर पुलिस की उस कार्यवाही को फर्जी बताते हुए रामबाई को बिना शर्त रिहा करने की बात कही है।

नक्सलियों के दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव गंगा ने नौ मार्च को प्रेसनोट जारी कर कहा था कि दो मार्च 2024 को बीजापुर जिला पामेड़ थाना अंतर्गत ग्राम जारपल्ली के जंगल से एक लाख की ईनामी महिला माओवादी कट्टम रामबाई को गिरफ्तार करने का पुलिस प्रशासन द्वारा प्रेसनोट जारी किया गया। मगर यह एक फर्जी गिरफ्तारी और सफेद झूठ के सिवा कुछ नहीं है।

प्रेसनोट में सचिव गंगा ने लिखा है कि सच्चाई यह है कि कट्टम रामबाई अपने परिजनों और गांव वालों के साथ मिलकर तेलंगाना मिर्ची तोड़ने और कुली मजदूरी करने गई हुई। इसी दौरान डीआरजी ने वहां से उठाकर पामेड़ थाना में एक झूठा केस दर्ज करके उन्हें जेल में बंद कर दिया।

ये घटना एक मात्र उदाहरण भर है। पिछले कई सालों से और अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को अवैध गिरफ्तारियां कर रहे हैं। प्रेसनोट में पड़ोसी राज्यों में कुली मजदूरी के लिए जा रहे लोगों की अवैध गिरफ्तारियां करके झूठे केसों फंसाकर जेल में भेजने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने व कमलापुर निवासी कट्टम रामबाई को बिना शर्त रिहा करने की बात लिखी गई हैं।

गेवरा खदान में कर्मचारियों ने किया काम बंद हड़ताल का एलान

मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन रहेगा जारी

कोरबा। गेवरा खदान में निजी कंपनी के कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल का एलान किया है। गेवरा सीजीएम कार्यालय के बाहर ठेका कर्मियों का प्रदर्शन जारी है। समान वेतन की मांग कर रहे हैं। साथ ही शोषण का आरोप भी लगाया है। आरोप लगाते हुए कहा है कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे।

कोरबा जिले में एसईसीएल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ एक निजी कंपनी के कर्मचारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। कोल माइंस अधीनियम,समान वेतन और मेडिकल की सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर रुंगटा ठेका कंपनी के कर्मचारियों ने पहले दो खदान में काम बंद कर दिया। फिर गेवरा सीजीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए है।

आपको बता दें,कि रुंगटा कंपनी खदान के भीतर कोयले का खनन काम करती है। ठेका कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से खदान के भीतर उत्खनन का काम पूरी तरह से ठप्प हो गया है। खदान के भीतर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। ठेका कर्मियों के द्वारा प्रदर्शन करने की सूचना मिलते ही पुलिस और विभागीय सुरक्षाकर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और स्थिती को नियंत्रण में लिया।

कर्मचारियों ने बताया कि काफी लंबे समय से रुंगटा कंपनी में काम करते आ रहे हैं। जिसमें अन्य चार और कंपनियां भी हैं। जो कोयला उत्खनन का काम करती हैं। सभी कंपनियों में अलग-अलग कर्मचारी है। जिनका वेतन अलग-अलग है। ऐसे में समान वेतन सबको नहीं मिल पा रहा है और न ही उनको मेडिकल सुविधा मिल रही है। इन बातों को लेकर वह हड़ताल करने के लिए बाध्य है।

इससे पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर निजी कंपनी और एसईसीएल प्रबंधन के समक्ष अपनी बातें रखी थी। लेकिन अब तक पूरी नहीं हो सकी। जिसे लेकर सभी कर्मचारी आक्रोशित है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दीपका थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची।

अयोध्या से लौटा श्रद्धालुओं का जत्था, राममय हुआ रेलवे स्टेशन

भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप ने किया स्वागत

जगदलपुर। पांच दिन पहले जगदलपुर करीब 1100 से अधिक रामभक्तों के जत्थे को लेकर ट्रेन अयोध्या रवाना हुई थी। आस्था स्पेशल ट्रेन सोमवार सुबह वापस लौटी। इस मौके पर एक बार फिर जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर माहौल भक्तिमय नजर आया। प्लेटफार्म पर ढोल-नगाड़े बज रहे थे, ट्रेन से उतरने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्टेशन पर मौजूद लोग भी जय श्रीराम के नारे लगा रहे थे। रामभक्तों का यह जत्था जिस उत्साह के साथ भजन कीर्तन करते और नाचते-गाते ट्रेन से रवाना हुआ था, उसी अंदाज में उनकी वापसी हुई। स्टेशन पर कई श्रद्धालु ढोल-नगाड़े की धुन पर नाचते नजर आए। उनके चेहरों पर रामलला के अलौकिक दर्शन का आनंद साफ झलक रहा था। जगदलपुर रेल्वे स्टेशन में भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप ने सभी श्रद्धालुओं का ढोल बजाकर व पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया।

इस मौके पर अनेक श्रद्धालुओं ने अपनी अयोध्या यात्रा के अनुभव भी साझा किए। रामलला की मनोहारी मूरत और राम मंदिर की दिव्यता और अयोध्या नगरी की भव्यता के किस्से उन्होंने लोगों को बताए। तमाम श्रद्धालुओं का यही कहना था कि रामलला के दर्शन कर जीवन धन्य हो गया। 500 वर्षों के इंतजार के बाद अब जाकर यह शुभ अवसर आया कि अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला विराजित हुए और हमें उनके दर्शन का पुण्यलाभ मिला।

आयोध्या दर्शन के पश्चात वापस जगदलपुर लौटे सुकमा के श्रद्धालुओं की टोली ने रामलला के दर्शन करने हेतु भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप द्वारा किये गए सहयोग हेतु उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि भगवान राम के दर्शन करके हम सभी धन्य हो गए। आपको बता दे कि छह मार्च को अयोध्या हेतु जगदलपुर से रवाना हो रही ट्रेन में सैकड़ो सुकमा के दर्शनार्थी विलंब के कारण छूट गए थे, जिन्हें भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप व अन्य भाजपा नेता सुरेश गुप्ता व संजय पांडे की मदद से उन्हें अन्य स्टेशन तक पहुंचाकर वापस सकुशल आयोध्या की ओर रवाना किया गया था।

हाथियों ने बरपाया कहर, बुजुर्ग दंपती को उतारा मौत के घाट

वन विभाग की टीम पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल क्षेत्र सरगुजा संभाग में इन दिनों हाथियों का उत्पात जारी है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के तहत एक गांव में सोमवार की अलसुबह दो दंतैल हाथियों ने वृद्ध ग्रामीण के घर को तोडना शुरु कर दिया। इसी बीच आवाज सुनकर घर से पति-पत्नी जैसे ही घर से बाहर निकले तभी हाथियों ने दोनों को घर के सामने ही कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी हाथियों ने उक्त दंपति का घर तोड़ा था। इधर सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम के ऊपर ग्रामीण भडक़ गए।

सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम दरहोरा निवासी हरिधन 69 वर्ष अपनी पत्नी नन्ही 66 वर्ष के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी, ऐसे में वृद्ध दंपती गांव से लगे जंगल के किनारे घर बनाकर रह रहे थे। रविवार की रात पति-पत्नी घर में सो रहे थे। इसी बीच सोमवार की अलसुबह करीब चीर बजे दो हाथी वहां पहुंचे और उनके घर को तोडने लगे। हाथियों की तेज दहाड़ सुनकर पति-पत्नी की नींद टूटी तो वे

घर से बाहर निकल ही रहे थे इसी बीच हाथियों ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। दंतैल हाथियों द्वारा वृद्ध दंपति को मार डालने की सूचना पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीण उनपर भडक़ गए। उनका कहना था कि हाथियों के गांव की ओर आने की सूचना उन्हें नहीं दी गई थी। कुछ देर तक चली बहस के बाद मामला शांत हुआ।

वन विभाग प्रतापपुर क्षेत्र के एसडीओ आशुतोष भगत ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों दंतैल हाथी अलग-अलग इलाके से अपने दल से भटककर यहां पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि एक दंतैल सीतापुर, लुंड्रा, अंबिकापुर और कल्याणपुर होते हुए जबकि दूसरा हाथी वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहे 34 हाथियों के दल से भटककर प्रतापपुर क्षेत्र में पहुंचा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

यात्री बस पर शरारती तत्वों ने किया पथराव

जगदलपुर। रविवार की देर रात रायपुर से जगदलपुर आ रही एक यात्री बस पर असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया। घटना के बाद मामले की जानकारी कोंडागाँव थाना प्रभारी को दी गई। जहां मौके पर पहुंची टीम को देख आरोपी भाग गए। मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि रायपुर से जगदलपुर आ रही एक यात्री बस पर रात करीब 11 से 12 बजे के बीच असामाजिक तत्वों के द्वारा कोंडागांव से लगे गांव में अचानक से पत्थर बाजी शुरू हो गई। जिस दौरान यह घटना घटित हुई। उस समय यात्री बस में सो रहे थे, अचानक से हुए इस हमले में एक बात यह रही कि किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार से कोई भी चोट नहीं आई। लेकिन घटना को देखते हुए बस चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को नही रोका और आगे बढ़ गया। बस में करीब 30 से अधिक यात्रियों के बैठे जाने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि एनएच 30 कोंडागांव के पास यह पहली घटना बताई जा रही है। इससे पहले इस तरह का कोई भी मामला सामने नही आया है।

सट्टा किंग संकेत अग्रवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोरबा। कोरबा में अवैध कारोबार पर एसपी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने संकेत अग्रवाल उम्र 30 वर्ष टीपी नगर पाटीदार भवन के पीछे चौकी निवासी के खिलाफ सीएसईबी पुलिस ने कार्रवाई की है। अवैध शराब, गांजा, एवं जुआ, सट्टा पर कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस टीम के द्वारा पहले भी सट्टा के तीन प्रकरणों में सट्टा खेलने वालों पर कार्रवाई की गई है। साइबर सेल कोरबा एवं चौकी सीएसईबी को सूचना मिली कि टीपी नगर कोरबा का संकेत अग्रवाल दादूराम हार्डवेयर दुकान के सामने अपने मोबाइल में ऑनलाइन दांव लगाकर सट्टा खेल रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा (रा पु से) नगर पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा भूषण एक्का (रापुसे) के मार्गदर्शन में घटना स्थल टीपी नगर कोरबा दादूराम हार्डवेयर दुकान के सामने पहुंचकर घेराबंदी की जो मुखबीर द्वारा बताए गये दादूराम हार्डवेयर के सामने एक व्यक्ति मिला जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम संकेत अग्रवाल उम्र 30 वर्ष पता टीपी नगर पाटीदार भवन के पीछे सीएसईबी कोरबा होना बताया।

बालोद में भीषण सड़क हादसा, चार लोगों की मौत

बालोद। बालोद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। ट्रक के नीचे दबने से कार सवार चार लोगों की मौत हो गई। थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि गाड़ी फंसी है। मौके पर पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है। जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुए सभी लोग दिल्ली के रहने वाले थे। वह किसी काम से बिलासपुर आए थे और बस्तर घूमने के लिए जा रहे थे। इस दौरान बालोद जिले के मरकाटोला घाट में हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी शवों को बाहर निकाला। शवों की शिनाख्त की जा रही है। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि सभी दिल्ली के हैं या फिर छत्तीसगढ़ के भी लोग शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक एस आर भगत ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ट्रक के नीचे दबने से कार बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हुई और कार सवार सभी लोगों की मौत हो गई।

छह लाख रु. से ज्यादा कीमत के मोबाइल फोन बरामद

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के वार्ड नबर 17 के रविदास चौक के पास सब्जी मार्केट से सब्जी लेकर घर जा रहे व्यक्ति के साथ चाकू की नोक पर मोबाइल फोन और 550 रूपये की तीन अज्ञात व्यक्तियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। जिसमे सिटी कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपीयों को पकड़ा और उनके पास से 20 नग मोबाइल कीमती छह लाख 50 हजार रूपये को बरामद किया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वहीं दो नाबालिक बालकों को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी से मिली जानकारी अनुसार, अंजनी कुमार पाण्डेय से 24 फरवरी को जब वह सब्जी लेकर घर जा रहा था तभी एक व्यक्ति पास आया और चाकू को दिखाकर 550 रु तथा मोबाइल को लूट किया उसके साथ दो अन्य साथियों के साथ भाग निकले की रिपोर्ट दर्ज सिटी कोतवाली में किया गया। जांच पड़ताल पर साइबर टीम और पुलिस टीम जुटी हुई थी। इस दौरान सूचना मिली की कुछ संदिग्ध लोग चांपा में एक किराए के मकान में रह रहे है।

भू माफियाओं में हड़कंप, सक्ती में जल्द निकलेगा बुलडोजर

सक्ती। भू माफियाओं का आतंक सक्ती में इस कदर बढ़ चुका है कि उन्हें अब शासन प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं रहा। ये कारोबारी खुलेआम सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिसके चलते सरकार को राजस्व की हानि भी उठानी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद जिला प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। सक्ती एसडीएम ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले 12 लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सक्ती एसडीएम पंकज डाहिरे ने बताया कि भू स्वामियों को 7 दिन का समय दिया गया है। जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। जरूरत पड़ने पर मौके पर जाकर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। एसडीएम के इस आदेश के बाद भूमाफियाओं की नींद उड़ी हुई है। सक्ती एसडीएम पंकज डाहिरे ने कहा 12 जगहों पर अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए जमीन की खरीदी बिक्री रोक दी गई हैं।

महासमुंद लोकसभा चुनाव में चलेगी मोदी की गारंटी या कायम रहेगा कांग्रेस का भरोसा?

- **कांग्रेस पर ब्रेक लगाने कभी भाजपा ने उतारा था साहू प्रत्याशी, पिछले 15 साल से दबदबा बरकरार**

गरियाबंद। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी का एलान होते ही मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है। भाजपा इस बार बसना क्षेत्र की ओबीसी वर्ग की महिला रूप कुमारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि कांग्रेस ने नेहले पे देहला फेंकते हुए ओबीसी वर्ग से ही साहू समाज के ताम्रध्वज साहू को अपना प्रत्याशी बना कर भाजपा का खेल बिगाड़ने की कोशिश की है। प्रत्याशी तय होते ही दोनों पार्टी में नाराजगी भी खुल कर सामने आई है। कांग्रेस से दावेदारी कर पीसीसी के प्रदेश महामंत्री रहे किसान नेता चंद्रशेखर शुक्ला ने कांग्रेस छोड़कर पार्टी को झटका दे दिया। कांग्रेस में साहू समाज से स्थानीय दावेदार माने जा रहे धनेंद्र साहू को टिकट नहीं दिया गया तो उनके समर्थक खुल के ताम्रध्वज को पैराशूट लैंडिंग बोलकर विरोध कर रहे हैं। इधर साहू समाज से भाजपा के 4 बड़े चेहरे की अनदेखी की आग भी भीतर से सुलग रही है। हालांकि भाजपा सत्ता में होने के साथ ही अनुशासन में सख्त है। इस लिहाज से नाराजगी खुल कर सामने नहीं आ रही है।

विधानसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा वोट कांग्रेस के पास

इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। दोनों दल से 4-4 विधायक हैं। लेकिन वोट के लिहाज से कांग्रेस आगे है। कांग्रेस से खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश, धमतरी के ओंकार साहू, बिंद्रांवागढ़ के जनक ध्रुव, सरायपाली से विधायक बनी चातुरीनंद को मिलाकर कांग्रेस ने कुल 6 लाख 97 हजार 187 वोट हासिल किए। तो वहीं भाजपा से

कुरूद विधायक अजय चंद्राकर, बसना के संपत अग्रवाल, राजिम के रोहित साहू, महासमुंद के योगेश्वर ने मिलकर 6 लाख 87 हजार 909 मत हासिल कर सके। कांग्रेस, भाजपा की तुलना में 9 हजार 278 वोटो से आगे है।

कांग्रेस पर ब्रेक लगाने भाजपा ने उतारा था साहू प्रत्याशी

1957 से अब तक इस सीट से 18 सांसद बने। जिसमें सबसे ज्यादा 7 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल के नाम दर्ज है। लोकप्रियता ऐसी थी कि 1989 का चुनाव वे जनता दल के बैनर से लड़े और भाजपा-कांग्रेस दोनों को अपना लोहा मनवाया था। भाजपा ने कांग्रेस पर ब्रेक लगाने के लिए 1991 में चंद्रशेखर साहू को अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन संत पवन दीवान की लोकप्रियता को कांग्रेस ने भुना लिया था। 1996 में भी दोनों का आमना-सामना हुआ। इस बार भी फायदा कांग्रेस को हुआ। लेकिन तीसरी बार 1998 के चुनाव में पवन दीवान को मात देने में चंद्रशेखर साहू सफल रहे। कांग्रेस ने 1999 में श्यामाचरण शुक्ल, तो 2004 में अजीत जोगी जैसे नेता को उतार सीट को बचाती रही। लेकिन 2009 के बाद लगातार साहू प्रत्याशी महासमुंद सीट पर भाजपा का परचम लहराते रहे। 2009 और 2014 में लगातार चंदू लाल साहू, तो 2019 में चुन्नीलाल साहू सर्वाधिक 50।42 प्रतिशत मत लेकर सांसद बने। यह दौर मोदी लहर का दौर माना जा चुका था। लिहाजा कांग्रेस से प्रत्याशी बने धनेंद्र साहू को 43।02 प्रतिशत वोट में ही संतोष होना पड़ा था।

अंतर्कलह का फायदा उठा सकती है कांग्रेस

दुर्ग के बाद सबसे बड़े साहू समाज का वोट बैंक महासमुंद लोकसभा में हैं। राजिम, धमतरी, महासमुंद, खल्लारी और कुरूद इन 5 विधानसभा सीटों पर साहू समाज का ज्यादा प्रभाव है। इस बार सांसद चुन्नीलाल साहू दो बार के सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू के अलावा संघ की ओर से सिरकट्टी आश्रम के पीठाधीश्वर गोवर्धन शरण ब्यास जो साहू समाज से आते हैं इनकी दावेदारी थी। समाज के 4 बड़े चेहरे को दरकिनार कर पार्टी ने इस बार महिला वंदन का कार्ड खेल दिया। इससे समाज में नाराजगी भी है। कांग्रेस द्वारा बनाई गई आंतरिक रिपोर्ट में इसका जिक्र भी है। लिहाजा सुलगे इस आग को हवा देकर कांग्रेस अपनी रोटी सेंकने में कामयाब हो सकती है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार कांग्रेस का भरोसा काम आएगा या फिर इस बार भी मोदी की गारंटी से कांग्रेस को अपने मजबूत सीट से हाथ धोना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने जगार-2024 'हस्तशिल्प और हाथकरघा' प्रदर्शनी का शुभारंभ किया

13 राज्यों के 130 हस्तशिल्पियों ने लगाए हैं स्टाल, सीएम साय ने 5 कारीगरों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से किया सम्मानित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आज जगार-2024 'हस्तशिल्प एवं हाथकरघा' प्रदर्शनी का दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ किया। पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट परिसर में आयोजित किए जा रहे इस प्रदर्शनी में देश भर के 13 राज्यों के 130 हुनरमंद हस्तशिल्पियों ने स्टॉल लगाए हैं। 10 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न कलात्मक वस्तुओं, हथकरघा वस्त्र सहित घरेलू उपयोग की वस्तुओं की स्टॉल लगाए गए है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव, संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा भी उपस्थित थे। अतिथियों ने स्टॉलों का अवलोकन कर शिल्पियों को प्रोत्साहित भी किया।

मुख्यमंत्री साय ने जगार-2024 के शुभारंभ समारोह में राज्य के पांच सिद्धहस्त शिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2021-22 से सम्मानित किया। इनमें बेलमेटल शिल्पी सुंदरलाल झारा ग्राम एकताल पोस्ट नेतनगर, विकासखण्ड पुसौर जिला रायगढ़, समीप विश्वकर्मा लौह शिल्पी ग्राम किड़ईछेपड़ा (ड़ोगरीगुड़ा) पोस्ट पलारी जिला कोण्डागांव-बस्तर, मन्धर कश्यप काष्ठ शिल्पी ग्राम भोण्ड (पाण्डूपारा) पोस्ट लामकेर जिला बस्तर, बृहस्पति जायसवाल गोदना शिल्पी ग्राम मुनगाडीह पोस्ट पाली जिला कोरबा और बाबी सोनवानी

भित्तीचित्र शिल्पी ग्राम सिरकोतंगा पोस्ट लहपटरा विकासखण्ड लखनपुर जिला सरगुजा को साल, श्रीफल, प्रमाण-पत्र, स्मृति चिन्ह और 25-25 हजार रूपए का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अतिथियों ने सिद्धहस्त शिल्पियों को प्रदान किए गए राज्य स्तरीय पुरस्कार की स्मारिका का विमोचन भी किया।

सीएम विष्णु देव साय ने जगार-2024 शुभारंभ समारोह में शामिल होने वाले सभी शिल्पकारों और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जगार मेले का शिल्पकारों को इंतजार रहता है। शिल्पियों के उत्पादों को यहां बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वें रायगढ़ के ग्राम एकताल कई बार गए है, इस ग्राम के शिल्पकारों की जीविका का साधन बेलमेटल शिल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेलमेटल, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, गोदना शिल्प, भित्ति चित्र के हुनरमंद शिल्पकार हैं और यही इनकी आजीविका का साधन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हस्तशिल्पों का विकास हो और इनके उत्पादों को अच्छा बाजार उपलब्ध हो इसके लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी। शिल्पकारों के उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदेश में स्थान चिन्हित कर बाजार की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हस्तशिल्प एवं हाथकरघा प्रदर्शनी में शिल्पकारों को अपने उत्पादों को दिखाने का और बिक्री करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री आमजनों से आग्रह किया है कि मेलें में आकर शिल्पकारों की कला को देखे और इनके उत्पादों की खरीदी भी करें। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि प्राचीन समय से ही छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति गौरवशाली और समृद्धशाली रही है। छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति विश्व स्तर पर पहुंचे इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वे वर्ष 2002 से जगार मेले में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्रों में हस्तशिल्प वहां के शिल्पकारों की आजीविका का साधन है। इन शिल्पकारों के उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य और राज्य के बाहर के शो-रूम और एजेंसियों से यह तय किया जाए कि उत्पाद के साथ शिल्पी का नाम और कोड नंबर का भी उल्लेख हो। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में वनवासियों की आजीविका का साधन बांस शिल्प भी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का बेलमेटल शिल्प, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, गोदना शिल्प की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है इसे हमें और आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड यशवंत कुमार, कलेक्टर रायपुर गौरव कुमार सिंह सहित विभागीय अधिकारी और विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकार भी उपस्थित थे।

प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहेगी

यह प्रदर्शनी 19 मार्च तक छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी, रायपुर में प्रतिदिन संध्या 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। यह प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ राज्य के सुप्रसिद्ध हस्तशिल्प बेलमेटल शिल्प (ढोकरा), लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प, कालीन शिल्प, शिशल शिल्प, गोदना शिल्प, तुमा शिल्प, टेराकोटा शिल्प, छींद-कांसा शिल्प एवं हाथकरघा वस्त्रों में कोसा साड़ियां, दुपट्टा, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल एवं कॉटन बेडशीट, चादरें, ड्रेस मटेरियल, सटिंग एवं विभिन्न प्रकार की खादी रेडीमेड वस्त्रों आदि प्रमुख है, इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से उत्तरप्रदेश लखनऊ की चिकनकारी, बनारसी साड़ी, ड्रेस मटेरियल, मध्यप्रदेश की चंदेरी, महेश्वरी साड़ियां एवं बाघ प्रिंट की ड्रेस मटेरियल एवं टीकमगढ़ की पीतल की मूर्तियाँ, पश्चिम बंगाल का जूटवर्क, कांथा वर्क तथा बंगाली साड़ियां सहित, पंजाब की फुलकारी और पंजाबी जूतियां, राजस्थान की चर्मशिल्प की मोजरी और एम्ब्राईडरी के सलवार सूट, दिल्ली की ज्वेलरी, हरियाणा पानीपत के बेडशीट, महाराष्ट्र के कोल्हापुरी चप्पल, बिहार के भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, जम्मू कश्मीर के शॉल एवं साड़ियाँ इस प्रकार कुल 13 राज्यों के विभिन्न शिल्पकलाओं और हाथकरघा सामग्री का विशाल संग्रह उपलब्ध रहेगा,जिसमें स्वयं शिल्पकार अपनी उन्नत शिल्पकला के हुनर का प्रदर्शन-सह-विक्रय करेंगे।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री से मिले मनरेगा कर्मी, प्रदेश में भी नियमितिकरण करने की मांग

रायपुर। प्रदेश के मनरेगा कर्मचारी

नियमितिकरण को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इस बार भाजपा सरकार से कर्मचारियों को बहुत उम्मीद हैं। राजस्थान मे वर्तमान भाजपा सरकार ने 4966 मनरेगा कर्मियों के लिए नियमित पदों के लिए पत्र जारी किया है। जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह क्षत्री के नेतृत्व मे प्रांतीय दल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजस्थान की भांति मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण किए जाने की मांग की। साथ ही मनरेगा कर्मचारियो ने कैबिनेट की बैठक मे संविदा कर्मचारियों के अवकाश को 18 से 30 दिवस करने के लिए भी आभार प्रकट किया। बता दें कि 7 मार्च 2024 को मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी समस्याओ और नियमितीकरण के सम्बंध मे मुख्यमंत्री से मुलाकात किया था। छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारियों मे भी अब नियमितीकरण की आस जगी है।

शिल्पकार अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति का कैसे बदला स्वरूप

रायपुर। रामलला की मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज रविवार को रायपुर पहुंचे। लोक में राम कार्यक्रम में अरुण योगीराज का सम्मान किया गया। रायपुर से वापस लौटने के बाद एयरपोर्ट पर अरुण योगीराज ने मीडिया से बात की। शिल्पकार अरुण योगीराज ने बताया कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना के बाद पूरे देश में बहुत प्यार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत प्यार मिला। यह हम शिल्पकारों को अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। मैं सभी छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रणाम करता हूं। अरुण योगीराज ने अयोध्या में विराजी रामलला की मूर्ति का स्वरूप परिवर्तित होने के सवाल पर कहा कि मूर्ति की स्थापना का विधि विधान है। उस जगह की पॉजिटिव एनर्जी है। पूरा विश्व रामलला की मूर्ति की स्थापना का इंतजार कर रहा था। शायद यही वजह है कि स्वरूप अलग दिख रहा है। 7 महीने तक काम चलता रहा। काफी मेहनत से मूर्ति बनाई हैं।

कालीबाड़ी छात्रों का स्वर्ण जयंती समारोह 31 मार्च को

रायपुर। सतता सुंदरी कालीबाड़ी उ. मा.

शाला के 1973-74 बैच के छात्र पचास साल बाद सपरिवार रविवार 31 मार्च को एकत्रित होंगे। इस स्वर्ण जयंती मिलने समारोह को यादगार बनाने के लिए छात्रों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वश्री प्रकाश लूनावत, राजेन्द्र खंडेलवाल, आनंद सुराना, सुजीत सन्याल, सुनील गनोदवाले, जगदीश मोटवानी, अरुण काठोटे, अशोक राय, सुहास देशपांडे, रमेश शर्मा, अरुण वर्मा, पन्नालाल गुप्ता, जगजीत सिंह वालिया, विजय वरहाडपांडे, डाकेश्वर बघेल, अजय चंद्रवंशी, कृष्ण कुमार राठौर, गुरूमुख अजवानी, आशीष दास गुप्ता तथा विवेकानंद त्रिपाठी उपस्थित थे। समारोह के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। 31 मार्च को सुबह शाला परिसर में सभी छात्रों का फोटो सेशन होगा। दोपहर बाद सभी छात्र तेलीबांधा स्थित एक होटल में सपरिवार एकत होंगे। समारोह में गुरूजनों के सम्मान के साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा गेम्स भी रखें जाएंगे। सभी छात्रों को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह देना भी निश्चित किया गया।

आरकेसी के सामने का शराब भट्ठी हटेगा: मूणत

शहीद चूड़ामणि वार्ड में 50 लाख में निर्मित हमर क्लीनिक, सामुदायिक भवन, मितानिन भवन का लोकार्पण

रायपुर। रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 7 के तहत शहीद चूड़ामणि वार्ड में जीई रोड में राजकुमार कॉलेज के सामने की शराब भट्टी को हटाने की नागरिकों की मांग को शीघ्र पूर्ण करवाने रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह को पत्र लिखकर इस सम्बन्ध में अतिशीघ्र कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्देश दे दिये है।

आज श्री मूणत ने उक्त जानकारी देते हुए रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के तहत नगर निगम जोन 7 के तहत शहीद चूड़ामणि वार्ड नम्बर 38 में पहुंचकर नागरिकों को आश्वस्त किया कि वार्ड पार्षद दीपक जायसवाल सहित समस्त वार्डवासियों की मांग के अनुसार अतिशीघ्र राजकुमार कॉलेज के सामने जीईरोड से शराब भट्टी को हटाने की कार्यवाही विभागीय कार्यवाही रायपुर जिला प्रशासन एवं आबकारी विभाग के माध्यम से की जाएगी। मूणत ने रायपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष श्रीमती मीनल चौबे, वार्ड पार्षद दीपक जायसवाल सहित नगर पालिक निगम जोन 7 जोन कमिश्नर जसदेव सिंह बाबरा, कार्यपालन अभियंता सुशील मोडेस्टस, स्वास्थ्य विभाग के सम्बंधित क्षेत्र के अधिकारियों, वार्डवासी गणमान्य जनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं, नवयुवकों की उपस्थिति में जनहित में जनसुविधा विस्तार की दृष्टि से शानदार सौगातों की झड़ी लगा दी। मूणत ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर निगम जोन नम्बर 7 के शहीद चूड़ामणि वार्ड क्रमांक 38 में आमा तालाब के समीप 25 लाख रूपये की लागत से नवनिर्मित स्वास्थ्य विभाग के हमर क्लीनिक भवन का फीता काटकर लोकार्पण करते हुए वार्डवासियों को लोक स्वास्थ्य सुविधा की शानदार सौगात दी। विधायक ने वार्ड क्रमांक 38 के क्षेत्र में नगर निगम द्वारा अधोसंरचना मद से 15 लाख रूपये की स्वीकृत लागत से नवनिर्मित नवीन सामुदायिक भवन की जनहित में जनउपयोग की दृष्टि से फीता काटकर शानदार सौगात निगम नेता प्रतिपक्ष एवं वार्ड नम्बर 38 के पार्षद के साथ मिलकर दी।

वार्ड नम्बर 38 में विधायक निधि मद से 5 लाख रूपये की स्वीकृत लागत से अवघडनाथ मन्दिर के पास निर्मित सामुदायिक भवन एवं आमापारा हॉट बाजार के समीप नगर निगम द्वारा सामान्य निधि मद से 5 लाख रूपये की स्वीकृत लागत से नवनिर्मित मितानिन भवन का फीता काटकर लोकार्पण करके मितानिन बहनों को शानदार सौगात दी। वार्ड पार्षद दीपक जायसवाल ने सभी वार्डवासियों की ओर से वार्ड में स्वास्थ्य विभाग के हमर क्लीनिक सहित निगम द्वारा निर्मित मितानिन भवन, दो सामुदायिक भवनों की वार्डवासियों को शानदार सौगात देने पर विधायक श्री राजेश मूणत, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष श्रीमती मीनल चौबे को हार्दिक धन्यवाद दिया।

भाजपा के जिहाद गांव वाले पोस्ट पर विजय शर्मा ने कांग्रेस को घेरा

रायपुर। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा के जिहाद गांव वाले पोस्ट पर कहा, पिछली बार जैसी सरकार चली है। उनके मुखिया जहां भी होंगे, ऐसा ही सोचा जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहता हूं कि सरकार पिछली बार जैसी चली है। जनता ने जैसे पीड़ा झेली है, समाज में जैसे विभेद उत्पन्न हुए हैं। आज अगर राजनांदगांव लोकसभा से प्रत्याशी हैं तो कोशिश उनकी वही रहेगी ऐसा लगता है।

इतना ही नहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, लव जिहाद और धर्मांतरण का विषय सबसे पूछना चाहिए। केवल हमसे क्यों पूछा जाता है। बस्तर में घटनाएं होती हैं, जिसमें धर्मांतरित होने के लिए बल का प्रयोग होता है। ऐसे होगा तो गलत है। धर्मांतरण पर पूरी कार्रवाई करेंगे और प्रावधानों के साथ करेंगे।

कई कांग्रेस नेताओं के भाजपा प्रवेश को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, बहुत से लोग यहां भी जुड़ना चाहते हैं। मगर बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि कौन कैसा है, यह समझना पड़ता है। तभी ज्वाइनिंग दी जाती है।

बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

■ कन्हैया कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास घेराव

रायपुर। सोमवार को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया कुमार रायपुर में थे। आज रायपुर में कांग्रेस बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।

कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में आकर जो गारंटी दी थी, उसे पूरा नहीं किया गया है। यही वजह है कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। इससे पहले दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस ने सब्जी और किराना का सामान खरीदकर महंगाई के खिलाफ विरोध जताया था। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार सरगुजा पहुंचे थे। अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कन्हैया ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। कन्हैया कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के पहले के लॉर्ड कर्जन की भूमिका के तहत इस समय देश में काम कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि लार्ड कर्जन ने 1905 में भारत का बंटवारा किया था। लेकिन आज के समय में दिल्ली में बैठे लॉर्ड कर्जन भारत को बांटने का काम कर रहे हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर 8 फरवरी के दिन कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी की जाति को लेकर भी सवाल उठाए थे।

रायपुर में राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम

निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने दिया खास सुझाव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में केन्द्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल शामिल हुए। राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायतीराज मंत्रालय कपिल मोरेश्वर पाटिल और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हितग्राहियों को उनके खाते में राशि ट्रांसफर किया।

इस दौरान भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत बस्तर और सरगुजा संभाग की अनुसूचित क्षेत्रों की 600 पंचायतों

में कंप्यूटर के लिए 3 करोड़ रुपये दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए किश्त की राशि ट्रांसफर की गई। इसमें कुल 15,714 हितग्राहियों को कुल राशि 49 करोड़ 21 लाख रुपये हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि सीधे ट्रांसफर किया गया। पंचायत स्तर पर युवाओं के ज्ञान वर्धन, शिक्षा उपलब्धता, उन्हें सशक्त बनाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर 833 ग्राम पंचायतों में ज्ञानोदय वाचनालय की स्थापना हेतु 25 करोड़ की राशि ट्रांसफर किया गया।

कार्यक्रम में पंचायती राज्य मंत्री का डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। ताकि उनके दिए सुझावों के अनुसार पंचायतों को और मजबूत बनाने की दिशा में काम हो सके।

राजनांदगांव से संतोष पांडेय जीत पाएंगे जनता का भरोसा या भूपेश दिखाएंगे अपनी जादूगरी

राजनांदगांव। राजनांदगांव लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद संतोष पांडेय को एक बार फिर मौका दिया और उन्हें चुनाव में खड़ा किया। इधर कांग्रेस ने भी राजनांदगांव सीट पर पूर्व सीएम और पाटन विधायक भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी के लिए राजनांदगांव सीट सबसे सेफ सीट मानी जाती है लेकिन इस बार कांग्रेस कैंडिडेट भूपेश बघेल के इस सीट से चुनाव लड़ने से समीकरण बदल सकते हैं।

संतोष पांडे का जन्म 31 दिसंबर 1967 को कबीरधाम जिले के सहसपुर में हुआ। उनके पिता का नाम शिव प्रसाद पांडेय और माता का नाम सोना देवी पांडेय है। सांसद संतोष पांडेय की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी पूरी तरीके से भाजपा से जुड़ी रही। पिता शिव प्रसाद पांडेय सहसपुर लोहारा मंडल के दो बार मंडल अध्यक्ष रहे। माता सोना देवी पांडेय अविभाजित मध्य प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य रही। इनका परिवर संघ से जुड़ा रहा।

सांसद संतोष पांडेय कृषक परिवार से आते हैं। एलएलबी की पढ़ाई की है। परिवार पर संघ का प्रभाव होने के कारण वे भी संघ से जुड़े। भाजपा के मंडल अध्यक्ष से लेकर राजनांदगांव जिला के युवा मोर्चा के दो बार अध्यक्ष रहे। भाजपा में दो बार प्रदेश महामंत्री के पद पर रहे। कृषि उपज मंडी कवर्धा के अध्यक्ष भी रहे। भाजपा शासन काल में खेल एवं युवा कल्याण आयोग के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। साल 2003 में विधानसभा परिसीमन होने से पहले वीरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव भी लड़ा। युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी रहे और दोनों विकास यात्रा के रथ प्रभारी रहे। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रांत के सह संयोजक रहे। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से 17वीं लोकसभा में सांसद बने। वर्तमान में वह राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में राजनांदगांव लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी है।

दुर्ग जिले के पाटन से विधायक और छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री बने। 23 अगस्त 1961 को दुर्ग जिले में नंदकुमार बघेल और बिंदेश्वरी बघेल के घर किसान परिवार में पैदा हुए। 80 के दशक में युवा कांग्रेस के सदस्य के रूप में राजनीति की शुरुआत की। महासचिव और प्रदेश कांग्रेस के समन्यवय भी बने। 1993 में पहली बार संयुक्त मध्यप्रदेश में पाटन विधानसभा के लिए चुने गए। साल 1990 से 1994 तक जिला युवा कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष रहे। साल 2000 में छत्तीसगढ़ गठन के बाद पाटन से विधायक चुने गए। साल

2003 में फिर से विधायक बने लेकिन साल 2008 का चुनाव हार गए। साल 2013 में फिर से पाटन से जीत दर्ज की। साल 2018 में 15 साल के भाजपा शासन काल को खत्म करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने।

राजनांदगांव लोकसभा सीट प्रमुख वीआईपी सीटों में से एक है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह यहां से विधायक हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट में 8 विधानसभा आते हैं। जिसमें राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खुज्जी, डोंगरगांव, मोहला मानपुर खैरागढ़, कवर्धा, पंडरिया शामिल है। इन 8 लोकसभा सीटों में 5 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इस लिहाज से देखे तो विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है।

राजनांदगांव लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ गठन के बाद से लगातार बीजेपी के कब्जे में ही रही। लोकसभा चुनाव 2009 में भाजपा के मधुसूदन यादव ने 54.17 प्रतिशत वोटों से जीत हासिल की और सासंद बने। यादव को 437721 वोट मिले जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के देवव्रत सिंह को 318647 वोट मिले और हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2019 में।

साल 2014 लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव विधायक रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह यहां से चुनाव लड़े और सांसद बने। अभिषेक सिंह को 643473 वोट मिले। अभिषेक सिंह को 56.15 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर वर्मा को इस चुनाव में 407562 वोट मिले। इनका वोट प्रतिशत 35.156 प्रतिशत रहा। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने संतोष पांडे को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने भोलाराम साहू को उम्मीदवार बनाया। संतोष पांडे को 662387 वोट मिले जबकि कांग्रेस के भोलाराम साहू को 550421 वोट मिले। 8.169 प्रतिशत वोटों के अंतर से भाजपा को जीत मिली।

लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे- आठ विधानसभा वाले राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में चार जिले राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़ छुईखदान गंडई,नवगठित मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला शामिल हैं। जहां मूलभूत सुविधाएं ही प्रमुख मुद्दे हैं। बेरोजगारों के लिए रोजगार सहित कोई बड़ा उद्योग राजनांदगांव जिले में नहीं है। बड़ा उद्योग नहीं होने के कारण युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। नवगठित दोनों जिले का विकास भी किया जाना है। वनांचल जिला होने के कारण वनांचल क्षेत्र में भी विकास होने हैं। यहां के युवा लगातार बड़ा उद्योग की मांग करते आए हैं, लेकिन अब तक कोई उद्योग खड़ा नहीं किया गया है।

राजनीतिक समीकरण- राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख लोकसभा क्षेत्र में से एक है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहां से विधायक है। इसके साथ ही कई पूर्व मंत्री और कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनांदगांव जिले से आते हैं। इस लिहाजा से यह जिला खास है। दोनों ही प्रमुख दलों ने एक बड़ा दाव यहां खेल है। भाजपा ने संतोष पांडे पर दाव लगाया है तो कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। बीते तीन चुनावों में भाजपा ही यहां से संसद में जाती रही, अब देखना होगा कि हाई प्रोफाइल सीट पर कांग्रेस कैसे वोटर्स को लुभाने में कामयाब होती है।

चुनाव पर मंडराता डीपफेक का खतरा

अजय कुमार

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आम चुनाव के लिए कमर कस रहा है। पिछले 75 वर्षों से भी अधिक अवधि में भारतीय चुनाव तंत्र ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। देश का यह तंत्र राज्य एवं केंद्र स्तर पर सरकारें स्थापित करता आया है। वर्तमान समय में कई चुनौतियां भी सामने आई है परंतु इनसे बेअसर भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने विभिन्न उपायों के जरिये- सचित्र मतदाता पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदान के तत्काल बाद मतदाता द्वारा सत्यापित किए जाने वाले विशिष्ट पत्र और चुनाव पर्यवेक्षक एवं चुनावी व्यय पर नजर रखने वाले तंत्र के जरिये अपना काम संजीदगी से किया है। मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए आयोग ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है। 2024 का आम चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए एक और नई चुनौती लेकर आया है और वह है डीपफेक (भ्रमित करने वाले वीडियो एवं सामग्री) के कारण पैदा होने वाले खतरे। यह चुनौती साधारण नहीं है क्योंकि इसके कई घातक एवं दूरगामी नतीजे हो सकते है। इसका कारण यह है कि डीपफेक लोगों की निर्णय लेने की शक्ति प्रभावित करते हैं और मूल तथ्य एवं मनगढंत सामग्री के बीच अंतर समाप्त कर देते हैं। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के एक रूप जेनेरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स (जीएएन) की मदद से तेजी से डीपफेक प्रसारित किए जा सकते हैं। इस हथकंडे से चतुर लोग भी धोखा खा सकते हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए इस्तेमाल में सहज जीएएन ऑनलाइन माध्यम में कुछ ही डॉलर में उपलब्ध है जिससे यह पूरा मामला और पेचीदा हो जाता है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के डीपफेक भी आने लगे हैं जो इस बढ़ते खतरे की गंभीरता का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कुछ लोग हथियार के रूप में कर रहे हैं। यहां पर भी शाब्दिक स्तर पर बदलाव या छेड़-छाड़ की हुई तस्वीरों के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। भ्रामक ऑडियो-वीडियो सामग्री से तथ्यों के साथ छेड़-छाड़ की आशंका और बढ़ जाती है। चुनाव के संदर्भ में बात करें तो डीपफेक चुनाव प्रक्रिया की प्रामाणिकता के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं। डीपफेक तैयार करने वाले लोग मतदान केंद्रों पर कब्जे की दुखद घटनाओं की याद दिलाते हैं। मगर डीपफेक बूथ पर कब्जा जमाने से भी अधिक खतरनाक हैं। ऐसे वीडियो तैयार करने वाले लोगों के पास कई हथकंडे होते हैं जिनमें विभिन्न मकसद के लिए संदर्भ आधारित फर्जी वीडियो भी शामिल हैं। इन वीडियो को खरीदने वाले लोगों में विदेशी शक्तियों से लेकर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी आदि शामिल होते हैं। डीपफेक का इस्तेमाल कर विदेशी शक्तियां चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालती हैं और चुनावी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाती हैं। खासकर, वे देश ऐसा करने की ताक में लगे रहते हैं जो भारत को एक मजबूत सरकार चुनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तकनीकी हस्तक्षेपों जैसे वॉटरमार्किंग, ब्लॉकचेन या क्रिप्टोग्राफी मतदाताओं की धारणा प्रभावित करने वाले डीपफेक पर अंकुश लगाने में कारगर नहीं होते हैं। भ्रामक खबरों का प्रसार अधिक होने की स्थिति में मानव की सोचने-समझने की क्षमता प्रभावित होती है जिसका असर यह होता है कि प्रामाणिक खबरों पर सनसनी पैदा करने वाली फर्जी सामग्री का दबदबा बढ़ जाता है। हालांकि, यह भी सच है कि डीपफेक का कोई पुख्ता इलाज नहीं है मगर तकनीक, नियमन एवं संचालन चुनावों पर इनके असर को कम कर सकता है। एक प्रभावी तरीका यह हो सकता है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सामग्री पर लगातार नजर रखी जाए और जब भी कोई फर्जी खबर या सामग्री सामने आए उन्हें तत्काल समय रहते हटा दिया जाए। ऑडियो-वीडियो सामग्री में छेड़-छाड़ पकड़ने के लिए एआई तकनीक मौजूद हैं मगर असल चुनौती सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होने वाली सामग्री की वैधता की पहचान वास्तविक समय में करने की है। एक व्यावहारिक कदम यह हो सकता है कि ऐसी पोस्ट पर नजर रखी जाए जो असाधारण तेजी से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही हैं।

'भाजपा ने ओवैसी को घेर लिया'

नीरज कुमार दुबे

देश भर में घूम-घूमकर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस बार खुद अपने गढ़ हैदराबाद में घिर गये हैं क्योंकि भाजपा ने आरएसएस कार्यकर्ता माधवी लता को उनके खिलाफ उतार दिया है। माधवी लता जिस तरह से अपनी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद से ओवैसी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं उससे हैदराबाद के सांसद की राजनीतिक जमीन हिल गयी है। इसीलिए आजकल ओवैसी जिम में पसीना बहा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बार मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ना है और समय निकाल कर अन्य प्रदेशों में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार भी करना है। हम आपको बता दें कि हाल में संपन्न तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जिस तरह एआईएमआईएम को अपने गढ़ हैदराबाद में झटका लगा था उसके चलते लोकसभा चुनाव के लिए ओवैसी काफी सतर्कता बरत रहे हैं।

जहां तक माधवी लता की बात है तो आपको बता दें कि वह आरएसएस कार्यकर्ता, पारंपरिक भारतीय महिला, उद्यमी, अस्पताल प्रशासक और एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तक हैं। हाल के समय तक राजनीतिक क्षेत्रों में उनका नाम कभी चर्चा में नहीं रहा था लेकिन जब भाजपा ने हैदराबाद से उन्हें लोकसभा सीट का उम्मीदवार घोषित किया तो वह रातोंरात सुर्खियों में आ गयीं। 49 वर्षीय कोम्पेला माधवी लता तीन बच्चों की मां हैं। जब उन्हें भाजपा उम्मीदवार बनाया गया तो वह खुद भी आश्चर्यचकित रह गयी थीं क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी कोई पैरवी नहीं की थी। ओजस्वी वक्ता और उस्मानिया विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर माधवी लता कहती हैं कि मेरी उम्मीदवारी से यह बात साबित हो जाती है कि भाजपा लोगों की क्षमताओं और उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों पर नजर रखती है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है।

हम आपको बता दें कि माधवी लता को उम्मीदवार बनाये जाने का कारण यह भी है कि एक तो वह महिला हैं और दूसरा मुस्लिम महिलाओं के बीच उन्होंने काफी काम किया है जिसके चलते वह उनके बीच काफी

लोकप्रिय हैं। इसके अलावा एक प्रखर वक्ता होना भी उनके पक्ष में गया है क्योंकि ओवैसी जिस तरह अपने भाषणों के जरिये लोगों को अपने पक्ष में करते हैं उसी तरह अपने भाषणों के जरिये उन्हें जवाब देने वाला प्रतिद्वंद्वी उनके खिलाफ चाहिए था। हम आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने चार दशकों से हैदराबाद लोकसभा सीट पर कब्जा बनाए रखा है। सलाहुद्दीन ओवैसी ने 1984 से 1999 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद से उनके बेटे असदुद्दीन हैदरबाद से सांसद हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट के तहत गोशामहल को छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्रों पर एआईएमआईएम का कब्जा है। गोशामहल से भाजपा के फायर ब्रांड नेता टी. राजा विधायक हैं। भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भगवंत राव पवार को अपना उम्मीदवार बनाया था जोकि ओवैसी से भारी अंतर से चुनाव हार गये थे। इस बार हैदराबाद से भाजपा प्रत्याशी तय करने में आरएसएस से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रमुख और संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने इस क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं के बीच काम कर रहीं माधवी लता का नाम सुझाया जिस पर पार्टी में सहमति बन गयी और उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हो गयी। खुद माधवी लता भी इस बात को मानती हैं कि उन्हें चुनाव में मुस्लिम महिलाओं का सहयोग मिलेगा। उनका कहना है कि अगर हिंदू-मुस्लिम मुद्दे को देखा गया होता तो भाजपा मुझे उम्मीदवार नहीं बनाती। उनका कहना है कि मैं मुस्लिमों के बीच काम करती हूँ और उन्हें अपना मानती हूँ। माधवी लता का कहना है कि मैं तीन तलाक की विरोधी रही हूँ और हिंदुओं से जुड़े विषयों को लेकर भी सक्रिय रही हूँ। पुराने हैदराबाद शहर के याकूतपुरा की संतोष नगर कॉलोनी में एक निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार में पली-बढ़ी लता माधवी कहती हैं कि वह हमेशा विभिन्न संस्कृतियों के बीच रहीं हैं।

माधवी लता ने अपनी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद मीडिया से कहा था कि मुझे 1980 के दशक में हुए सांप्रदायिक दंगों ने डरा दिया था। उन दंगों ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि लोग किसी की जान लेकर अपनी नफरत क्यों व्यक्त करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वर्षों के अनुभव के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसके पीछे आम आदमी नहीं बल्कि एक राजनीतिक खेल है। उनका कहना है कि एक आम आदमी चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, वह हिंसा नहीं चाहता। उन्होंने ओवैसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो कभी भी दोनों समुदायों के बीच शांति नहीं चाहते हैं। माधवी लता का कहना है कि यह लोग लंबे समय से सत्ता में जमे हैं लेकिन इन्होंने अपने समुदाय के लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया। मौजूदा सांसद को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि मैं पुराने शहर की हर गली में प्रचार करूंगी और अगर मुझ पर एक भी पत्थर फेंका गया तो असदुद्दीन ओवैसी जवाबदेह होंगे।

माधवी लता का कहना है कि मेरे विरोधियों को चाहिए कि वह मुझे बराबरी का मुकाबला करने की अनुमति दें। उनका कहना है कि हमें धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए और लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। उनका कहना है कि मैं चुनाव प्रचार में धर्म की बात नहीं करूँगी। माधवी लता का दावा है कि हैदराबाद में ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां मतदाताओं को धमकाया जा रहा है और पोलिंग एजेंट स्वतंत्र रूप से काम करने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं चुनाव आयोग से माँग करूँगी कि पर्याप्त संख्या में बल तैनात किया जाये और मतदान प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाये। उनका कहना है कि वह हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र के 1996 मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क करेंगी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हो गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माधवी लता का यह भी कहना है कि मतदाता सूची से 2 लाख से अधिक हिंदू मतदाताओं को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को लगता है कि पुराने हैदराबाद शहर में बहुत सारे मुसलमान हैं इसलिए ओवैसी जीतते रहते हैं लेकिन इस बार यह मिथक टूट जायेगा क्योंकि मुझे सभी समुदायों का समर्थन मिलेगा। माधवी लता का कहना है कि वह चुनाव प्रचार के दौरान सीएए और तीन तलाक के बारे में लोगों की गलतफहमियां भी दूर करेंगी।

जहां तक ओवैसी की बात है तो आपको बता दें कि वह राष्ट्रीय स्तर पर अपना सियासी वजूद कायम करने के लिए पूरा जोर भले लगा रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार तो उनको अपने गृह राज्य तेलंगाना विधानसभा चुनावों में ही झटका लग गया जब उनकी पार्टी की सीटों की संख्या घट गयी। इसके अलावा, हाल के चुनावों की बात करें तो ओवैसी ने बिलकीस बानो को आधार बनाकर गुजरात में अपनी सियासत शुरू करने की कोशिश की थी लेकिन भाजपा ने गुजरात के दाहोद जिले की लिमखेड़ा विधानसभा सीट पर भी जीत दर्ज की जहां कभी 2002 के दंगों की पीड़िता बिलकीस बानो रहा करती थीं। ओवैसी हैदराबाद से बाहर निकल कर हर जगह अपने पांव फैलाना चाह रहे हैं लेकिन जनता उन्हें उल्टा लौटा दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने बड़े-बड़े दावे कर डाले थे। हिजाब को मुद्दा बना दिया था लेकिन यूपी की जनता ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया था। इससे पहले बिहार में जरूर उनकी कुछ सीटें आ गयी थीं लेकिन एक को छोड़कर बाकी विधायक राष्ट्रीय जनता दल में भाग गये। ओवैसी परिवार की बात करें तो आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ही भड़काऊ भाषण नहीं देते बल्कि उनके छोटे भाई और तेलंगाना के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी तो कभी-कभी अपने बड़े भाई से भी आगे निकल जाते हैं। अभी हालिया तेलंगाना विधानसभा चुनावों के दौरान भी उन्होंने रात दस बजे के बाद भाषण देने से रोकने वाले पुलिस अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा था कि %%मुझे रोकने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है।%% अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस अधिकारी को धमकाते हुए कहा कि अगर वह अपने समर्थकों की तरफ इशारा कर दें, तो उन्हें यहां से दौड़ कर भागना पड़ेगा। इससे पहले भी अकबरुद्दीन ओवैसी कई विवादित बयान दे चुके हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे पर जाना अपनी शान समझते हैं और हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-29)

गतांक से आगे...

क्योंकि मन ही संसार है, जो वासना और अन्य क्लेशों से प्रदूषित है। जो इन भौतिक शरीरों से मुक्त हो जाता है उसे भवन्ता कहा जाता है। 66॥ जब मन की कल्पना की जाती है, तो देहधारी आत्मा शरीर बन जाती है। जो व्यक्ति शरीर की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वह कभी भी शरीर के कर्तव्यों से कलंकित नहीं होता। 67॥ यह कल्प को क्षणिक बना देता है, क्षण कल्प को अपने भीतर ले लेता है। मुझे विश्वास है कि यह मानसिक आनंद की दुनिया है। 68 उस ने बुरे काम करना न छोड़ा, न उसका नाश हुआ, न वह एकाग्र हुआ मन नष्ट न होने पर भी बुद्धि द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। राग-द्वेष आदि के विकारों से दूषित चित्त ही जगत् है। वही चित्त समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है, तभी इसे जगत् का अन्त यानी मोक्ष की प्राप्ति होना कहा जाता है। मन के द्वारा शरीर की भावना किये जाने पर ही आत्मा देहात्मक बनती है। जब वह शारीरिक वासनाओं से मुक्त होती है, तभी वह (मन) शरीर के धर्मों में लिप्त नहीं होती। यह मन ही कल्प को क्षण बना देता है और क्षण में कल्पत्व भर देता है। अत: मेरी समझ में यह जगत् केवल मनोविलास अर्थात् मन का खेल मात्र ही है। जो मनुष्य दुश्चरित्रता से विलग नहीं हुआ है, एकाग्रचित्त नहीं है और जिसका चित्त अभी शान्त नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष को आत्मसाक्षात्कार नहीं होता। उस आनन्द स्वरूप, द्वन्द्वों से परे, गुणरहित (गुणों से परे), सत् स्वरूप, चिद्घन परब्रह्म को अपना-निज स्वरूप जान लेने के पश्चात् मनुष्य को किञ्चित् भी भय नहीं होता। जो महान् से महानतम एवं श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम, तेज:स्वरूप, शाश्वत, कल्याण-प्रद, सर्वज्ञ, पुराणपुरुष, सनातन, सर्वेश्वर तथा सभी देवगणों के द्वारा सम्पूजित एवं उपास्य है, वह अविनाशी ब्रह्म मैं हूँ ऐसा निश्चय महात्माओं के लिए मुक्ति का माध्यम होता है।

क्रमश: ...

रामकृष्ण परमहंस ब्रह्मर्षि, देवर्षि एवं त्रिकालदर्शी थे

ललित गर्ग

अंगुलियों पर गिने जाने योग्य कुछ महान् व्यक्तियों को समय-समय पर भारत की रत्नगर्भा वसुंधरा ने पैदा किया, जिनकी आध्यात्मिक चेतना एवं सिद्धियों से समूची दुनिया चमत्कृत होती रही है। जो युग के साथ बहे नहीं, युग को अपने बहाव के साथ ले चले। ऐसे लोग सच्चे जीवन के धनी और जीवन-चैतन्य से ओतप्रोत है। वे स्वयं आगे बढें, जन-जन को बढ़ाते चलें। ऐसे महापुरुषों-युगपुरुषों-युगांतरकारी सिद्धपुरुषों का जीवन साधनामय होता है और जन-जन को वे साधना की पगडंडी पर ले जाते हैं, प्रकाश स्तंभ की तरह उन्हें जीवन पथ का निर्देशन देते हैं एवं प्रेरणास्रोत बनते हैं। जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से न सिर्फ स्वयं को प्रतिष्ठित किया वरन् उनके अवतरण से

समग्र विश्व मानवता धन्य हुई है। इसी संतपुरुषों, गुरुओं एवं महामनीषियों की शृंखला में एक महापुरुष हैं रामकृष्ण परमहंस।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक महान संत, उच्चकोटि के साधक, विचारक, समाज सुधारक एवं सिद्धपुरुष थे। वे स्वयं भगवान नहीं थे, लेकिन भगवान से कम भी नहीं थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने सभी धर्मों को एक बताते हुए उनकी एकता पर जोर दिया था। उनका मानना था कि सभी धर्मों का आधार प्रेम है। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति की। अपनी साधना से रामकृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। वे ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न-भिन्न साधन मात्र हैं। भारत का जन-जन रामकृष्ण परमहंस की परमहंसी साधना का साक्षी है, उनकी गहन तपस्या के परमाणुओं से अभिषिक्त है यहां की माटी और धन्य है यहां की हवाएं जो इस भक्ति और साधना के शिखरपुरुष के योग से आप्लावित है। संसार के पूर्णत्व को जो प्राप्त हैं, उन इने-गिने व्यक्तियों में वे एक थे। उनका जीवन ज्ञानयोग, कर्मयोग एवं भक्तियोग का समन्वय था।

यो तो रामकृष्ण के जीवन में अनेक गुरु आये पर अन्तिम गुरुओं का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। जिनमें एक थी भैरवी जिन्होंने उन्हें अपने कापालिक तंत्र की साधना करायी और दूसरे थे श्री तोतापुरी उनके अन्तिम गुरु। गुरु तोतापुरी सिद्ध तांत्रिक तथा हठ योगी थे। उन्होंने रामकृष्ण को परमशिव के निराकार रूप के साथ पूर्ण संयोग की दीक्षा दी।

श्री रामकृष्ण परमहंस की भक्ति एवं साधना ने हजारों-लाखों को भक्ति-साधना के मार्ग पर अग्रसर किया। उनके जादुई हाथों के स्पर्श ने न जाने कितने व्यक्तियों में नयी चेतना का संचार हुआ, उन जैसे आत्मद्रष्टा ऋषि के उपदेशों का अचिन्त्य प्रभाव असंख्य व्यक्तियों के जीवन पर पड़ा। उनके प्रेरक जीवन ने अनेकों की दिशा का रूपान्तरण किया। उनकी पावन सन्निधि भक्ति, साधना एवं परोपकार की नयी किरणें बिखेरती रही अत: वे साधक ही नहीं, साधकों के महानायक थे। वे ब्रह्मर्षि और देवर्षि थे- साधना-भक्ति के नये-नये प्रयोगों का आविष्कार किया इसलिये ब्रह्मर्षि और ज्ञान का प्रकाश बांटते रहे इसलिये देवर्षि। माँ काली की कृपा से वे त्रिकालदर्शी महापुरुष बन गए थे।

पाकिस्तान में शीर्ष अदालत ने मान ली गलती

मरिआना बाबर

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में काली सलवार-कमीज और काले कोट पहने खड़े थे। उनकी कोट की जेब में विशुद्ध सिंधी रंगों वाला एक प्रिंटेड रूमाल था। बिलावल अपनी कानूनी टीम के साथ दिवंगत नाना यानी पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले में फैसले का इंतजार कर रहे थे। यह अदालत की लाइव कार्यवाही थी और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग इसे देख रहे थे।

प्रधान न्यायाधीश ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा, %जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई और न ही संविधान की उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया गया। लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट में अपील की कार्यवाही के दौरान निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 4 एवं 9 में निहित उचित प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया, जबकि संविधान के अनुच्छेद 10ए में उचित प्रकिया के तहत एक अलग और मौलिक अधिकार के रूप में निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी दी गई है।

फैसला सुनते ही बिलावल रो पड़े और जेब से रूमाल निकालकर अपने आंसू पोछे। उनकी टीम के सदस्यों और समर्थकों की आंखों में भी आंसू थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए उनकी आवाज कांप रही थी। जब उनकी मां बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी, तब भी मैंने छोटे से बिलावल को सार्वजनिक रूप से रोते हुए नहीं देखा था। अब बिलावल बड़े हो गए हैं और पीपीपी के अध्यक्ष हैं। वह न केवल अपने नाना, बल्कि पीपीपी के पहले अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले की सुनवाई देख रहे थे। मैंने हमेशा कहा है कि सैन्य

तानाशाह और भ्रष्ट व अनैतिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुल्फिकार अली भुट्टो को दी गई फांसी एक न्यायिक हत्या थी। जैसा कि किसी ने टिप्पणी की कि इतिहास ने पहले ही जुल्फिकार अली भुट्टो को दोषमुक्त कर दिया है। भुट्टो के मुकदमे की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताजा रुख स्वागतयोग्य है। लेकिन शीर्ष अदालत को अपनी नाक के नीचे होने वाली सुनवाई की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। देर से न्याय होना न्याय नहीं होने के समान है।

सुप्रीम कोर्ट ने जब भुट्टो को फांसी देने का फैसला सुनाया था, तब बिलावल का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला आसिफ अली जरदारी द्वारा भुट्टो की फांसी के खिलाफ 2011 में दायर मुकदमे के संदर्भ में था। इस ताजे ऐतिहासिक फैसले की पृष्ठभूमि यह है कि वर्ष 2011 में राष्ट्रपति रहते हुए आसिफ अली जरदारी ने संविधान के अनुच्छेद 186 के तहत भुट्टो की मौत के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले का अनेक राजनेताओं एवं वकीलों ने स्वागत करते हुए इसे 'ऐतिहासिक' बताया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, इतिहास की गलतियों को सुधारना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन उस गंभीर गलती को स्वीकार करना नया इतिहास है और इससे नई परंपरा स्थापित हुई है। उन्होंने आगे कहा कि पिछली गलतियों को सुधारकर और दुश्मनी को खत्म करके ही राष्ट्रीय एकता और विकास को बढ़ाया जा सकता है।

इस बीच बिलावल की बहन आसिफा भुट्टो ने कहा कि आखिर भुट्टो की 'न्यायिक हत्या' के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी न्यायिक हत्या के 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, जो मुल्क के लिए एक बड़ी उम्मीद थे, को एक क्रूर एवं षड्यंत्रकारी तानाशाह द्वारा इस दुनिया से खत्म कर दिया गया। आसिफा बेनजीर भुट्टो की सबसे छोटी संतान हैं और हाल ही में एक दूसरे कारण से चर्चा में थीं।

उनके पिता आसिफ अली जरदारी और भाई बिलावल भुट्टो हाल में हुए चुनाव में सिंध से दो सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों पर जीत गए। उम्मीद है कि उनमें से एक सीट खाली होने के बाद आसिफा वहां से चुनाव लड़कर सांसद बनेंगी। यह एक अनूठी बात होगी कि जरदारी, बिलावल एवं आसिफा एकसाथ निचली सदन में उपस्थित होंगे। मुल्क के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं है, जब कोई पिता और उनकी दो संतान एक ही समय में सांसद हों। आसिफा भुट्टो ने आगे कहा, %शीर्ष अदालत के ताजा फैसले ने जुल्फिकार अली भुट्टो को सही साबित किया है। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूं, जिन्होंने जीवन भर अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए अथक संघर्ष किया। चार दशकों के बाद आखिरकार न्याय की जीत हुई है। जुल्फिकार भुट्टो की दूसरी नातिन फातिमा भुट्टो, जो प्रसिद्ध लेखिका हैं, ने कहा, यह पाकिस्तान के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री के खिलाफ किया गया ऐतिहासिक अन्याय था। हम अदालत के सर्वसम्मत फैसले का स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं कि ऐसा अन्याय दोबारा कभी न दोहराया जाए।

लेकिन वकील हसन ए नियाजी ने जो कहा, वह पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट और नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है- यह मानना कि जेडए भुट्टो को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित रखा गया, एक स्वागतयोग्य निर्णय है, लेकिन जिन संरचनात्मक मुद्दों ने ऐसा घोर अन्याय होने दिया, वे पाकिस्तान की राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं। एक निर्दोष राजनेता को एक ताकतवर सैन्य तानाशाह और उससे प्रभावित अदालत ने फांसी पर लटका दिया। इसी वजह से प्रधान न्यायाधीश ईसा ने टिप्पणी की कि हमारे न्यायिक इतिहास में कुछ ऐसे मामले हैं, जिन्होंने लोगों को मन में यह धारणा बनाई है कि या तो भय या पक्षपात ने कानूनी ढंग से न्याय देने की प्रक्रिया को बाधित किया है। इसलिए हमें आत्म-जिम्मेदारी की भावना से, विनम्रता के साथ अपनी पिछली गलतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और यह सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कानून के प्रति अटूट निष्ठा के साथ न्याय दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब तक हम अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक खुद को सुधार नहीं सकते और न ही सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

आज का इतिहास

1884 पहली महिला अमेरिकी राज्य कॉलेज की स्थापना मिसिसिपी की गयी।
1894 कोका कोला को पहली बार के लिए बोतलों में बेचना शुरू किया गया।
1912 जूलियट गॉर्डन लो ने लड़कियों के लिए एक युवा संगठन की स्थापना की जो यूएसए के गर्ल स्काउट्स में विकसित हुआ।
1921 तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली ने इस्तिकलामार्सी को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, गीत के साथ कवि मेहमत अकीफ़रौसी द्वारा लिखित गीत और ज़ेकी örngör द्वारा संगीत दिया गया है।
1927 जॉन बैरीमोर अभिनीत साहसी फिल्म द थियोडिंग रॉग प्रकाशित की गयी।
1928 कैलिफोर्निया में बने सेंट फ्रांसिस डैम के टूट जाने से आई बाढ़ के कारण 600 लोग मारे गए।
1934 एस्टोनियाई सेना द्वारा समर्थित, कॉन्स्टेंटिन पाट्स ने एरा ऑफ साइलेंस की शुरुआत करते हुए एक तख्तापलट का मंचन किया।
1948 कोस्टा रिकान सिविल युद्ध शुरू हुआ
1952 ब्रिटिश राजनयिक हेस्टिंग्स इस्माय को नाटो के पहले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।
1954 फिनलैंड और जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की स्थिति खत्म की।
1968 मॉरीशस ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की।
1970 अमेरिका में मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष की गयी।
1993 1993 की मैक्सिको की खाड़ी पर बने सेंचुरी के तूफान, इसकी ऊंचाई पर इसका प्रभाव सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी का लगभग 40 प्रतिशत था।
1995 बर्मिंघम में आइस पेयर्स चैंपियन में राडका कोवारिकोवा और रेने नोवोटनी ने जीत हासिल की।
1995 प्लैटोव और ग्रिटशुक ने आइस डांस चैंपियनशिप बर्मिंघम जीता।
2008 अमेरिकी वायुसेना ने विश्व के पहले स्टील्थ लड़ाकू विमान एफ़-117 को अपने बेड़े से हटाया।
2008 विश्व की सबसे लम्बी आयु की समझी जाने वाली महिला वारवा सेमेनिकोवा का रूस में 117 वर्ष की आयु में निधन हुआ।
2011 भूकंप और सुनामी के बाद, जापान खोज और बचाव प्रयासों में 50,000 आत्मरक्षा बलों के कर्मियों को तैनात करता है।
2012 परीक्षण चलने के बाद चीन के हाई स्पीड रेलवे खंड का एक भाग।
2013 2008 की शुरुआत से 2010 के वसंत तक अपने हैंडलिंग या वायरलेस डेटा पर .7 मिलियन का जुर्माना चुकाने के बाद, Google एक गोपनीयता मुकदमे को निपटाने के लिए सहमत हो गया।
2013 रोम, इटली में, रोमन कैथोलिक कार्डिनल पोप बेनेडिक्ट सोलहवें के उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के लिए एक सम्मेलन में मिलते हैं।
2014 चीन ने मलबे के उपग्रह चित्र जारी किए जो संभवत: 8 मार्च को एक मलेशियाई एयरलाइंस की उड़ान के लापता होने से जुड़ा हुआ है।
2014 अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा यूक्रेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, यात्सेनुक से मिले और यूक्रेन के साथ रूस के साथ संघर्ष करने की कसम खाई।

राहुल की यात्राएं नहीं रोक पा रही कांग्रेस में निराशा

अजय सेतिया

राहुल गांधी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने और पार्टी को जोड़े रखने के लिए शुरू की थी। उसे काफी सफलता भी मिली थी, लेकिन अपनी उसी यात्रा के दौरान दो विदेश यात्राएं करके उन्होंने अपनी सफलता को विफलता में बदल लिया। अब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी उन्होंने वही गलती दोहराई है, इसलिए लालू यादव को उन्हें कहना पड़ा कि वह विदेश यात्राएं कम करें। राहुल गांधी की बार बार की विदेश यात्राओं से उनकी राजनीतिक गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं। लोकसभा उम्मीदवारों का चयन करने के लिए हुई कांग्रेस की पहली केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक में उनके नदारद रहने पर भी उनकी राजनीतिक गंभीरता का पता चलता है। जब वह अपनी भारत जोड़ो यात्राओं के दौरान विदेश यात्राएं कर सकते हैं, तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की चयन बैठक में शामिल होना क्यों टाला गया।

पहले कहा गया था कि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग से जुड़ेंगे, लेकिन वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी बैठक से नहीं जुड़े। अपनी इन भारत जोड़ो यात्राओं के दौरान उन्होंने तीन विदेश यात्राएं तो की, लेकिन इस दौरान हुए संसद सत्र में वह लगभग पूरी तरह गायब रहे। कहते हैं कि दिल्ली में सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसी लिए नरेंद्र मोदी ने 2014 में उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा था, इसके साथ ही वह गुजरात की वडोदरा सीट से भी चुनाव लड़े थे। मोदी के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का भाजपा को बहुत फायदा हुआ, वह 80 में से 71 लोकसभा सीटें जीत गई। 2019 में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के स्वघोषित उम्मीदवार थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था। भले ही वह अमेठी में हार गए, लेकिन उनके केरल से चुनाव लड़ने का कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ, राज्य में कम्युनिस्ट सरकार होने के बावजूद कांग्रेस केरल में लोकसभा की 20 में से 15 सीटें जीत गई।

भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर उम्मीदवारी घोषित कर दी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश की क्रमशः अमेठी और रायबरेली सीट से उम्मीदवारी घोषित नहीं की है। जबकि राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में दो बार की भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो कांग्रेस को उनकी जीत पर कोई आशंका नहीं होनी चाहिए थी। असल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्राएं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह पैदा नहीं कर पाई हैं। कांग्रेस ने । मार्च को केन्द्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में 50 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए थे, लेकिन अगले दिन शुक्रवार को सिर्फ 39 नामों का एलान हुआ, क्योंकि 11 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से आनाकानी कर दी। इतना ही नहीं, केन्द्रीय चुनाव समिति के सदस्यों छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को जबरदस्ती टिकट थमाया गया है। चुनाव समिति के सदस्य सचिन पायलट से भी कहा गया कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें, लेकिन वह तैयार नहीं हैं।

केसी वेणुगोपाल लोकसभा का पिछ्ला चुनाव नहीं लड़े थे, उनकी अलाप्पुझा सीट पर जिसे उम्मीदवार बनाया गया था, वह चुनाव हार गए। इसलिए कांग्रेस ने

उन्हें ही अलाप्पुझा से चुनाव लड़ने को मजबूर किया, जहां से वह 2009 और 2014 में चुनाव जीते थे। केसी वेणुगोपाल को 2022 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनाया गया था। उनके अभी चार साल बाकी पड़े हैं। अगर वह केरल से लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, तो उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा। उनकी खाली होने वाली सीट पर कांग्रेस जीत नहीं सकती, क्योंकि अब राजस्थान में भाजपा बहुमत में है। वेणुगोपाल ने यह कह कर कांग्रेस की पोल खोल दी कि हम लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सांसद पहुंचाना चाहते हैं। यह कह कर जो बात उन्होंने छुपाई, वह यह है कि कांग्रेस लोकसभा में विपक्ष का आधिकारिक दर्जा हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इन सब घटनाओं से स्पष्ट है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में फेल हो जाने के बाद कांग्रेस ज़िंदा रहने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है।

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बावजूद कांग्रेस से पलायन रूक नहीं रहा। लोक दिखावे के लिए भले ही भारत जोड़ो यात्रा का मकसद मोदी सरकार की ओर से कथित तौर पर समाज में पैदा की गई खाई को भरना बताया जा रहा हो, लेकिन यह हर कोई जानता है कि इसका असली मकसद कांग्रेस से पलायन रोकना और राहुल गांधी को रिलांच करना था। कांग्रेस इन दोनों ही मकसदों में नाकाम रही है। उनकी यात्राओं के दौरान ही कांग्रेस से पलायन जारी है। शायद ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है, जहां से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर भाजपा या अन्य दलों में न जा रहे हों। कांग्रेस अपने नेताओं के पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने का कारण उनका ईडी और सीबीआई से डर बताकर भाजपा पर सत्ता का दुरूपयोग बताती रहती है। लेकिन ऐसा कह कर वह यह भी बता रही होती है कि सत्ता में रहते हुए उनके नेताओं ने जम कर भ्रष्टाचार किया था, जो अब बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मान लिया कि अशोक चव्हाण पर भ्रष्टाचार का मामला था, लेकिन मिलिंद देवड़ा पर कौन सा केस था। केरल के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी या करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल पर कौन से आरोप थे। ऐसे अनेक उदाहरण है जहां बेदाग़ कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। जैसे नरसिम्हा राव सरकार में संसदीय कार्यमंत्री रहे सुरेश पचौरी का राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मध्यप्रदेश से गुजर जाने के बाद भाजपा में शामिल होना। सुरेश पचौरी के साथ इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल भी कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले छिंदवाडा के एक हजार से ज्यादा कांग्रेस के छोटे बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे।

इसी तरह राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान से गुजरने के बाद गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे लालचंद कटारिया, पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल, खिलाड़ी लाल बैरवा सब भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले पूर्व मंत्री महेंद्र जीत सिंह मालवीय भाजपा में शामिल हुए थे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान ही गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अंबरीश ढेर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। क्या इन सब पर ईडी और सीबीआई का दबाव था, क्या इनमें से किसी के भी खिलाफ कोई पूछ्ताछ या केस चल रहा था? इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस के सभी नेता ईडी और सीबीआई के डर से भाजपा में शामिल हो रहे हैं। असल में ज्यादातर नेताओं को गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस का, और कांग्रेस के साथ अपना राजनीतिक भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है।

साहित्य संवर्द्धन में साहित्य अकादमी का महत्वपूर्ण योगदान

गोविंद मिश्रा

भारत सरकार ने स्वायत्त साहित्यिक संथा के रूप में साहित्य अकादमी (नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स) की स्थापना का आधिकारिक निर्णय दिसंबर 1952 में लिया था और 12 मार्च, 1954 को इसका उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। इस वर्ष हम इस महत्वपूर्ण संस्था की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साहित्य अकादमी को आधिकारिक रूप से इस प्रकार परिभाषित किया गया है- 'भारतीय साहित्य के सक्रिय विकास के लिए कार्य करनेवाली एक राष्ट्रीय संस्था, जिसका उद्देश्य उच्च साहित्यिक मानदंड स्थापित करना, भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों को समन्वित करना एवं उनका पोषण करना तथा उनके माध्?यम से देश की सांस्कृतिक एकता का उन्नयन करना होगा।' इस संस्थान की प्रमुख विशिष्टता यह है कि इसका प्रबंधन और संचालन लोकतांत्रिक ढंग से साहित्यकारों द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में जितनी भाषाएं शामिल हैं, उनसे संबंधित रचनाओं का पाठ होता है, सेमिनार होते हैं तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। बिना किसी भेदभाव के सभी भाषाओं के लिए पुरस्कार दिये जाते हैं। अगर हिंदी के लिए पुरस्कार की राशि एक लाख रुपये है, तो कोंकणी के लिए भी इतनी ही राशि दी जाती है। साहित्य अकादमी में कई श्रेणियां हैं, जिनमें लेखकों को शामिल किया जाता है। सामान्य परिषद सबसे शक्तिशाली इकाई है, जिसमें लगभग सौ सदस्य होते हैं। ये सदस्य सभी प्रांतों से आते हैं। राज्य सरकारें तीन नाम भेजती हैं, जिनमें से एक को पिछली सामान्य परिषद द्वारा अगले पांच वर्षों के लिए चुना जाता है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों, भाषाओं की सेवी संस्थाओं, प्रकाशकों, केंद्र सरकार और विभिन्न अकादमियों आदि के प्रतिनिधि भी सामान्य परिषद में होते हैं। साथ ही, एक प्रतिष्ठित साहित्यकार को भी चुना जाता है। सामान्य परिषद से ही कार्यकारी मंडल को बनाया जाता है। यह मंडल मुख्य रूप से संस्थान को संचालित करता है। पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियां हैं। प्रतिष्ठित साहित्यकारों को सीनियर फेलोशिप दी जाती है। ऐसे साहित्यकार समय-समय संस्थान को सलाह देते हैं। इस प्रकार बिना किसी नौकरशाही के साहित्यकार ही भारतीय साहित्य के संवर्द्धन का कार्य करते हैं। कोई भी स्वायत्त संस्था हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, कार्यपालिका यानी शासन द्वारा उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास हमेशा होता है। उन्हें लगता है कि पैसा सरकार का लग रहा है, तो निर्णय भी उन्हीं को करना चाहिए। साहित्य अकादमी संसद द्वारा पारित अपने संविधान से मार्गदर्शन लेती है। विभिन्न पद चुनाव द्वारा निर्धारित होते हैं। ऐसे में हस्तक्षेप की कोशिशें अभी तक काफी हद तक कामयाब नहीं हो पायी हैं। मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि पूरी स्वायत्तता रहती है, पर बहुत स्वतंत्रता से काम होता है। दखल यह होता है कि संस्कृति मंत्रालय के बहाने सरकार कभी कभी कुछ काम सौंप देती है, जो अकादमी कर देती है। साहित्य अकादमी नयी पीढ़ी के रचनाकारों को स्थान देने के लिए प्रयासरत है। उदाहरण के लिए, अकादमी में हिंदी भाषा का संयोजक होने के नाते मैंने यह तय किया है कि जहां भी कार्यक्रम हों, उनमें युवा पीढ़ी के साहित्यकारों को रचना पाठ या वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया जाए। अभी इंदौर में उपन्यासों पर कार्यक्रम होना है, जिसमें सेमिनार के साथ-साथ रचना पाठ भी होगा।

एक और परिवार मोदी सरकार की गारंटी का ले रहा पूरा आनंद

रामचंद्र गुहा

विगत एक मार्च, 2024 को, द हिंदू के ऑनलाइन संस्करण में जागृति चंद्रा की एक रिपोर्ट इस शीर्षक के साथ छपी -'अनंत अंबानी की प्री-वेडिंग पार्टी के लिए जामनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिला'। उसमें बताया गया कि कैसे सशस्त्र बलों द्वारा संचालित जामनगर के छोटे हवाई अड्डे को 25 फरवरी से 5 मार्च तक, दस दिनों के लिए 'अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा' घोषित किया गया था। ऐसा तीन दिवसीय प्री-वेडिंग पार्टी में बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, रिहाना, इवांका ट्रंप और कई पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे वैश्विक दिग्गजों का स्वागत करने के लिए किया गया था। मैंने जागृति चंद्रा की प्रभावशाली रिपोर्ट पढ़ी और फिर सोशल मीडिया पर टिप्पणियां देखने गया। जैसा कि इस समय अपेक्षित था, एक तरफ, सरकार के समर्थकों द्वारा कहा गया कि कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तानी आगंतुकों की सुविधा के लिए 2011 में चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर भी ऐसा ही किया था। लेकिन तब ऐसा क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए किया गया था, कोई निजी शादी नहीं थी।

एक तर्क यह भी था कि अंबानी परिवार ने हजारों भारतीयों को रोजगार दिया और दूसरा तर्क यह कि ऐसा इसलिए किया गया, ताकि आने वाले विशिष्ट अतिथियों को उचित सम्मान और सुरक्षा दी जा सके। दूसरी ओर, सोशल मीडिया के एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की -'अडानी और अंबानी के लिए भारत में जीवन स्वर्ग जैसा है और हममें से बाकी लोगों के लिए यह नरक है।'

एक अन्य ने टिप्पणी की - 'वसुधैव कुटुंबकम', जिसका अर्थ है 'दुनिया एक परिवार है', जैसी महान कहावत को 'मैं, मेरे अमीर दोस्त और उनके मित्र एक परिवार हैं' के रूप में फिर से लिखा गया है। एक दूसरी टिप्पणी की गई कि जामनगर हवाई अड्डे का नया स्वरूप इसलिए प्रभावित हुआ, क्योंकि 'एक युवा अमीर बच्चा दुनिया भर से कुछ प्रसिद्ध लोगों को आमंत्रित करके अपने निजी चिड़ियाघर का प्रदर्शन करना चाहता है।' जिस निजी चिड़ियाघर का उल्लेख किया गया है, वह 'राधा कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट' नामक संगठन द्वारा चलाया जाता है।

इस ट्रस्ट और इसकी गतिविधियों को 2021 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके सक्षम बनाया गया था, जिससे निजी चिड़ियाघरों के निर्माण और हाथी जैसी लुप्तप्राय जंगली प्रजातियों को पकड़ने, कहीं लाने-ले जाने और बिक्री को प्रोत्साहित करने की अनुमति मिली।

लेखिका और वन्यजीव संरक्षणवादी प्रेरणा सिंह बिंद्रा के अनुसार, पहले के कानून ने स्पष्ट रूप से संरक्षित प्रजातियों के व्यावसायिक लेन-देन को नकार दिया था, लेकिन अब संशोधन के बाद जीवित बंदी हाथियों को इस सामान्य निषेध से बाहर रखा गया है, जिससे उनकी व्यावसायिक खरीद-बिक्री जैसी एक बड़ी खामी रह गई है। यह एक संरक्षित जंगली जानवर हाथी को व्यापार योग्य वस्तु के रूप में पेश करता है और इसलिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के उद्देश्य और भावना के विपरीत है।

यह कानून में गंभीर विसंगति है, जिसे ठीक किया जाना चाहिए। जून 2022 में न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में एक ही महीने में आठ मामलों का जिक्र किया गया था, जहां कथित तौर पर तस्कर गिरोहों द्वारा असम से जंगली हाथियों की तस्करी के लिए जाली हस्ताक्षरों का उपयोग करके नकली अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास किया गया था। इनमें से सात मामलों में जामनगर में अंबानी द्वारा संचालित ट्रस्ट के लिए हाथियों के परिवहन के प्रयास किए गए थे। फरवरी, 2024 के अंतिम सप्ताह में अनंत अंबानी ने दावा किया कि राधा कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट में अब दो सौ से अधिक 'बचाए गए' हाथी हैं।

हालांकि, ऐसी अटकले हैं कि इनमें से अधिकतर हाथियों को कथित तौर पर अवैध रूप से जंगल में पकड़ लिया गया था और बाद में बिचौलियों की मदद से 'खरीदा' गया था। एक पशु अधिकार कार्यकर्ता ने मुझसे कहा कि जंगली प्रजातियों को घर देने, पुनर्वास करने और देखभाल करने के उनके प्रयासों का स्वागत होना चाहिए, लेकिन इसने पूर्वोत्तर से सैकड़ों हाथियों को अंबानियों तक ले जाने के लिए पुरानी पशु तस्करी नेटवर्क योजना को फिर से सक्रिय किया है। सम्मानित पारिस्थितिकी विज्ञानी रवि चेल्लम ने अंबानी चिड़ियाघर की तुलना एक व्यक्तिगत 'स्टांप संग्रह' से की है, जो वन्यजीव संरक्षण के वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त उद्देश्यों में कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता है।

वन्यजीव वैज्ञानिकों ने तीन सवाल उठाए हैं। सबसे पहले, इतने सारे जंगली हाथियों को जामनगर में क्यों ले जाया गया, जो एक शुष्क औद्योगिक क्षेत्र है और इस वन-प्रेमी जानवर की भलाई के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? दूसरा, इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक समानांतर नियामक प्रणाली क्यों बनाई गई? तीसरा, हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक आवासों में ऐसी सुविधाएं बनाने के लिए राज्य के वन विभागों के साथ काम क्यों नहीं किया गया? जब मैं छोटा था, तो तब के कांग्रेस शासन का वामपंथी आलोचकों द्वारा 'टाटा/बिड़ला सरकार' कहकर उपहास किया जाता था।

फिर भी निश्चित रूप से 1950 और 1960 के दशक में अपने प्रभाव और शक्ति के चरम पर जे.आर.डी. टाटा या घनश्याम दास बिड़ला ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वे जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी से अपने कारखानों के निकटतम हवाई अड्डे को पारिवारिक विवाह के लिए 'अंतरराष्ट्रीय दर्जा' दिलवा सकते हैं, न ही वे उन्हें एकल परिवार चिड़ियाघर के पक्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को मौलिक रूप से बदलने के लिए राजी कर सकते थे। लेकिन अब चीजें अब बिल्कुल अलग हो गई हैं। जैसा कि अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम ने तर्क दिया है, एक समान खेल का मैदान बनाने, जिसमें सभी उद्यमियों को सफल होने का समान मौका मिले, सरकार ने हाल के वर्षों में एक नए तरह के पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है।

गठबंधन धर्म कांग्रेस ने नहीं निभाया या ममता ने?

अजय सेतिया

ममता बनर्जी ने इंडी एलायंस की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का एकतरफा एलान कर दिया। यह शुरू से ही स्पष्ट था कि वह बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ किसी तरह का चुनावी गठबंधन करके उन्हें बंगाल की खोई हुई जमीन पर फिर से लौटने का मौक़ा नहीं देंगी। पटना में हुई विपक्ष की पहली बैठक के बाद जब सीताराम येचुरी की ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए तस्वीर वायरल हुई थी, तो बंगाल के कम्युनिस्ट काडर ने तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की थी। बंगाल में दोनों पक्षों के काडर में राजनीतिक दुश्मनी खून खराबे की हद तक है, इसलिए वे माकपा महासचिव सीताराम येचुरी या भाकपा महासचिव डी. राजा को ममता के साथ खड़ा नहीं देख सकते।

तब माकपा के नेताओं को बंगाल में जाकर कहना पड़ा था कि वे तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे। कम्युनिस्टों ने बंगाल के साथ साथ यह भी साफ़ कर दिया था कि वे केरल में भी कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। इंडी एलायंस के लिए यह एक सही समय था कि कम्युनिस्टों को गठबंधन से बाहर रख कर विपक्षी मोर्चा बनता, जैसे कि 2004 में यूपीए बना था। कम्युनिस्टों ने 2004 से 2008 तक यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। 2008 में जब अमरीका के साथ परमाणु ईंधन समझौते के कारण कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस लेकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, तो उसके बाद ममता बनर्जी यूपीए में शामिल हुई। 2009 का लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी ने यूपीए के साथ गठबंधन करके लड़ा क्योंकि कम्युनिस्टों का कांग्रेस से रिश्ता टूट चुका था। कांग्रेस के कम्युनिस्ट मोह के कारण ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। 2009 के चुनाव के बाद वह कम्युनिस्टों के समर्थन के बिना बनी यूपीए सरकार में दुबारा रेल मंत्री भी बनी, इससे पहले एनडीए में रहते हुए भी वह वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थी।

इससे ममता और कम्युनिस्टों की राजनीति को समझा जा सकता था। कांग्रेस अगर 2008 में धोखा देने वाले कम्युनिस्टों को इंडी गठबंधन से बाहर रखती, तो पश्चिम बंगाल में उसे अधीर रंजन के घोर ममता विरोधी होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में दिक्कत नहीं आती। कांग्रेस दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। न बंगाल में ममता ने उन्हें कोई सीट दी, न केरल में कम्युनिस्टों ने उन्हें कोई सीट दी। ममता बनर्जी ने लंबी राजनीति के तहत कांग्रेस को बंगाल में अलग थलग किया है। वह देश भर में कम्युनिस्ट विरोध की राजनीति करना चाहती हैं, जबकि कांग्रेस बिना कम्युनिस्ट चलना नहीं चाहती, हालांकि कम्युनिस्ट सिर्फ केरल तक सिमट कर रह गए हैं। तृणमूल कांग्रेस को फिर से कांग्रेस के मुकाबले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए ममता बनर्जी ने बिहार और गुजरात में पाँव फैलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बिहार के दो नेताओं शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आज़ाद को, तथा गुजरात के क्रिकेटर युसूफ पठान को पश्चिमी बंगाल में चुनाव मैदान में उतार दिया है।

कांग्रेस में भी ऐसे कई नेता हैं, जिनका मानना है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया है। श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के मुखर समर्थक होकर कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने के कारण छह साल के लिए कांग्रेस से निकाले गए प्रमोद कृष्णम खुलेआम कहते हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी बनाकर रख दिया है। बाकी राज्यों में जहां इंडी गठबंधन टूट गया है, वहां के अलग अलग कारण हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल और केरल में इंडी गठबंधन टूटने का कारण कांग्रेस का कम्युनिस्ट मोह है। पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार और पंजाब में इंडी गठबंधन टूटने का दूसरा बड़ा कारण कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर लापरवाही भी है। ममता बनर्जी की तरह बिहार में नीतीश कुमार जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग की मांग कर रहे थे, लेकिन लालू यादव भीतरघात की राजनीति करते हुए नीतीश कुमार की सरकार गिरा कर अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की राजनीति कर रहे थे। जिसे सही वक्त पर भांप कर नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन ही छोड़ दिया।

राजनीतिक गठबंधन के दो बेसिक रूल हैं, या तो पहले सीट शेयरिंग हो, या चुनाव के बाद कार्यक्रम आधारित गठबंधन हो। इंडी एलायंस इन दोनों रूल का पालन नहीं कर रहा था। गठबंधन कर लिया, लेकिन सीट शेयरिंग नौ महीने तक टली रही। क्षेत्रीय दल पहले दिन से कह रहे थे कि मीटिंग मीटिंग छोड़ो, पहले सीट शेयरिंग करो। लेकिन कांग्रेस के मन में बेईमानी थी, इसलिए सीट शेयरिंग को छोड़ कर राहुल गांधी को जन समर्थन लेने के लिए यात्रा पर भेज दिया। यह क्षेत्रीय दलों पर दबाव बनाने की रणनीति थी कि कांग्रेस ज्यादा मजबूत है, इसलिए उसे उनके राज्यों में ज्यादा सीट चाहिए। इसलिए बेईमानी की नींव पर खड़ा इंडी एलायंस चुनावों से पहले ही अपनी ताकत खो चुका है। जबसे देश में गठबंधन की राजनीति शुरू हुई है, हम पिछले 35 सालों से देख रहे हैं कि हर चुनाव से पहले गठबन्धनों में रि-एलायनमेंट होता है। एनडीए 1998 से कायम है, लेकिन हर चुनाव में उसके साथ कई दल छोड़कर जाते रहे, कई नए दल जुटते रहे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 2004 तक का चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन 2009 का चुनाव यूपीए के साथ गठबंधन करके लड़ा। 2004 में लोकसभा चुनावों के बाद बना यूपीए टूट चुका है। उसकी जगह जो इंडी एलायंस बना उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल किए गए, जबकि इससे पहले कम्युनिस्ट किसी भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे।

सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय विशेषाधिकार पर बदला अपना फैसला

सुधांशु रंजन

सांसदों -विधायकों के विशेषाधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यों वाली एक संविधान पीठ ने अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि रिश्वतखोरी अपराध है, जिसे संसदीय विशेषाधिकार का कवच हासिल नहीं है। इस तरह उसने लगभग 26 साल पूर्व पी वी नरसिंह राव बनाम सीबीआई मामले में इसी अदालत की पांच सदस्यों वाली संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को खारिज कर दिया। उस मामले में तीन जजों ने बहुमत से फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 105 (2) के तहत सांसदों द्वारा संसद में कही गई बातों और उनके द्वारा दिए जाने वाले वोट को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह बड़ा ही तकनीकी फैसला था। इसे स्वीकार करना हमेशा कठिन रहा क्योंकि घूस लेना संसदीय कार्यवाही का हिस्सा नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरतअंगेज यह व्यवस्था थी कि जिसने घूस लेकर मतदान नहीं किया, उसे विशेषाधिकार का लाभ नहीं मिलेगा। उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। अब शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि विशेषाधिकार वहीं लागू होगा जो संसदीय कार्यवाही का अभिन्न हिस्सा है। अन्यथा नागरिकों का एक अलग वर्ग तैयार हो जाएगा, जिसे कानून से ऊपर माना जाने लगेगा। यह सारा मामला शुरू हुआ 2012 में, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने राज्यसभा चुनाव में एक स्वतंत्र उमीदवार से घूस लिया, परंतु वोट अपने दल के प्रत्याशी को दिया। सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोपपत्र दायर किया। सीता सोरेन ने हाईकोर्ट में इसे यह कहते हुए चुनौती दी कि एक विधायक होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत उन्हें पूर्ण सुरक्षा हासिल है। उन्होंने पी वी नरसिंह राव मामले का हवाला देते हुए अपने विरुद्ध की गई कार्रवाई को खत्म करने की मांग की। हाईकोर्ट ने उनकी दलील ठुकरा दी। तब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2019 में तीन जजों की एक पीठ ने नरसिंह राव मामले में दिए गए फैसले से असहमति जताते हुए इसे एक बड़ी संविधान पीठ को भेज दिया, जिसने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया। सांसदों-विधायकों को सुरक्षा देने के ऐतिहासिक कारण हैं। भारत ने शासन के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है। इंग्लैंड में पहले लगभग सभी अधिकार सम्राट के पास होते थे। सांसदों को मामूली बातों के लिए जेल भेज दिया जाता था। 1397 में थॉमस हैक्सी ने हाउस आफ कॉमंस में एक विधेयक पेश किया, जो स्वीकार हो गया। इसमें सम्राट रिचर्ड द्वितीय के ऊपर प्रहार किया गया था। हाउस आफ लॉर्ड्स ने इसका संज्ञान लेते हुए आनन-फानन हैक्सी को देशद्रोही करार दिया और उन्हें मृत्यु दंड सुनाया। लेकिन वह फांसी के फंदे से बच गए क्योंकि आर्चबिशप ने उन्हें अपना क्लर्क बता दिया। इसके पहले 1376 में स्पीकर पीटर डी ला मेयर को उनके आचरण के लिए जेल भेज दिया गया था और सम्राट एडवर्ड तृतीय के जीवन काल में उनकी रिहाई नहीं हुई। 1512 में स्ट्रोड नामक एक सांसद को स्टैनरी कोर्ट द्वारा जेल भेजा गया क्योंकि उन्होंने कुछ विधेयक संसद में पेश किए थे जिन्हें राजा ने खारिज कर दिया था। स्ट्रोड को तीन सप्ताह बाद रिहा कर दिया गया और एक कानून पारित किया गया कि सांसदों को सदन में अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होगी। कुछ भी बोलने या करने के लिए उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। एलिजाबेथ प्रथम ने संसद के विशेषाधिकार को खत्म करना चाहा। 1629 में इलियट, हौलिस और वेलेंटाइन को संसद के अंदर देशद्रोही भाषण देने का दोषी माना गया। किंतु चार्ल्स द्वितीय के काल में हाउस आफ लॉर्ड्स ने उस फैसले को पलटते हुए व्यवस्था दी कि संसद में जो भी कहा जाता है, उस पर निर्णय संसद ही करेगी। 1689 में बिल ऑफ राइट्स में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि संसद के अंदर अभिव्यक्ति और बहस की आजादी को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी।

बर्फ चबाने या शराब पीने से भी खराब हो सकते हैं आपके दांत

एक्सपर्ट बता रहीं हैं डेंटल हेल्थ के अनदेखे खतरे

अगर आप चम्मच पकड़ने, धागा काटने या अखरोट तोड़ने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं, तो इन आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। इनके अलावा हार्ड या सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आपके दांतों को बहुत तेजी से खराब कर सकती हैं।

क्या आपने कभी सुना है कि रोजमर्रा की कई आदतें आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं? बतौर डेंटिस्ट हमारे पास अक्सर रोगी दांतों के टूटने, मसूड़ों में तकलीफ, दांत पीसने जैसी शिकायतें लेकर आते हैं। ये आदतें पूरी जिंदगी लोगों को प्रभावित करती हैं, उन्हें दर्द, असहजता, दांतों की विकृति की समस्या रहती है। आपके दांतों और मुंह से जुड़ी कुछ ऐसी ही हानिकारक आदतों के बारे में नीचे बताया गया है।

नाखूनों को चबाना

नाखूनों को चबाने से जबड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि आप काफी लंबे समय तक असामान्य स्थिति में रखते हैं और इससे दांत टूटने का भी खतरा रहता है। नाइट गार्ड का इस्तेमाल, नेलपॉलिश लगाना या फिर टॉपकोट से नाखूनों को चबाने की आदत दूर करने में मदद मिल सकती है।

बर्फ चबाना

बर्फ और इनैमल दोनों ही क्रिस्टल होते हैं और जब दो सख्त चीजें एक-दूसरे को दबाती हैं, तो एक हमेशा दूसरे को क्षतिग्रस्त कर देता है। इससे दांत में फ्रैक्चर या फिर फिलिंग डैमेज हो सकती है। पेय लेते समय स्ट्रॉ का इस्तेमाल या फिर बर्फ का इस्तेमाल ना करने से आप अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं।

तंबाकू का सेवन

धूम्रपान या वैपिंग से मसूड़ों की समस्याओं, दांतों के खराब होने, दांत झड़ने, मुंह की दुर्गंध, बार-बार मुंह सूखना और मुंह के कैंसर का काफी खतरा रहता है। काफी सारे उपचार से तंबाकू को छोड़ने में मदद मिल सकती है और दांतों के खराब होने, मसूड़ों की समस्याओं, दांत के गिरने, मुंह की दुर्गंध को दूर किया जा सकता है। साथ ही निकोटीन पैचेस का इस्तेमाल भी मददगार हो सकता है।

पेय /सोडा पीना

पेय से भरे बोतल या फिर सिपिंग कप से पेय पीने से दांत के इनैमल नष्ट हो सकते हैं। बुलबुले वाले ड्रिंक्स की जगह सादा पानी पिएं और सोने से पहले सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूस लेने से बचें।

शक्कर युक्त चीजें लेना

खाने के बीच में उच्च शक्करयुक्त चीजें खाने से मुंह में बैक्टीरिया पनपने लगता है, जिससे दांत खराब होने लगते हैं। संतुलित आहार के साथ पर्याप्त पानी इससे बचाव में मदद कर सकता है।

टूथपिक का इस्तेमाल

चर्चित मान्यताओं से उलट,दांतों में फंसा हुआ खाना बाहर निकालने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करने से आपके मसूड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है और दांतों के बीच बेवजह जगह बनती है। पानी का कुल्ला, पारंपरिक थ्रेड फ्लॉस या फिर इंटरडेंटल ब्रश से मुंह की अच्छी साफ-सफाई बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

जीभ काटना या पीयर्सिंग

धातु की पीयर्सिंग पर गलती से या फिर जानबूझकर दांत लगाने से दांतों को नुकसान पहुंचता है। मसूड़ों की तरफ पीयर्सिंग को रगड़ने से वो भी ढीले हो जाते हैं और दांत गिर सकते हैं। ओरल कैंसर से बचने के लिए जीभ पर पीयर्सिंग कराने से बचना चाहिए।

अत्यधिक शराब का सेवन

शराब की वजह से मुंह सूखता है, जिससे लार मुंह के बैक्टीरिया को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। इसकी वजह से मुंह से बदबू आना और आपके दांतों पर कीड़े लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है। शराब अम्लीय होती है, जोकि इनैमल को नष्ट कर देती है। ज्यादा मात्रा में कार्बोनेटेड स्पार्कलिंग पानी पीकर इससे बचाव किया जा सकता है।

दांतों को पीसना या कटकटाना

अनजाने में की जाने वाली इस हरकत से दांतों को नुकसान हो सकता है और मांसपेशियों में दर्द या जबड़ों का मूवमेंट सीमित हो सकता है। आराम देने वाली एक्सरसाइज और नाइट गार्ड की मदद से इस आदत को रोका जा सकता है।

दांतों का हाथ या औजार की तरह उपयोग करना

कई सारे लोग कलम, सुइयों, नाखून, कपड़ों के पिन को पकड़ने के लिए अपने दांतों को तीसरे हाथ की तरह इस्तेमाल करते हैं या फिर नट्स को फोड़ने, पैकेट खोलने या तारों को काटने के लिए ऐसा करते हैं। जब भी दांतों का इस्तेमाल चबाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है तो जबड़े को चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है या फिर दांतों में क्रैक आ सकता है। अपने दांतों को भोजन चबाने के अलावा किसी और काम के लिए इस्तेमाल ना करें।

डेंटिस्ट के पास न जाना

इन बुरी आदतों के अलावा, दांतों की देखभाल से बचते रहना एक ऐसी बुरी आदत है जोकि मुंह की सेहत को नुकसान पहुंचाता है। दांतों की जांच में देर करना या दांतों के दर्द को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन यह अपने आप कभी नहीं जाता। इससे बेहतर है, दांतों की समस्याओं का उचित इलाज कराएं। आपके शरीर में दांत ही एकमात्र एक ऐसा अंग है जोकि अपने आप ठीक नहीं होता। अगली बार जब भी आप अपने डेंटल अपॉइंटमेंट से बचने की कोशिश करें या फिर उसे रीशेड्यूल करें- उससे पहले एक बार जरूर सोच लें।

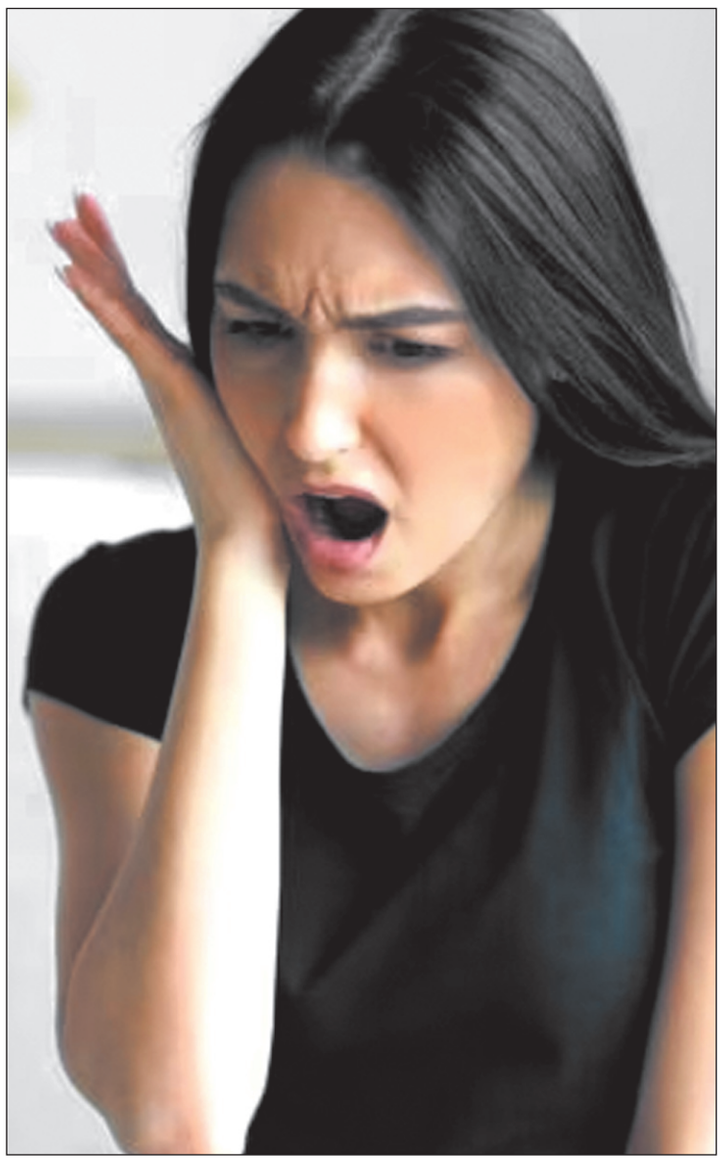

कलरिंग से डैमेज हो रहे हैं बाल, तो उन्हें हेल्दी बनाए रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

बालों को नया और अनोखा लुक देने के लिए लोग कई प्रकार के तरीके अपनाते हैं। कोई हेयर स्आइलिंग से बालों को इनोवेटिव लुक देता है, तो किसी को हेयर कलर पसंद है। दरअसल, इन दिनों हेयर कलरिंग काफी ट्रेंडिंग है। मगर बालों को नया लुक देने के अलावा उनकी देखरेख भी बेहद ज़रूरी है। अक्सर वे लोग जो हेयर कलर अप्लाई करते है, उन्हें बालों में रफनेस, स्कैल्प इचिग और हेयरफॉल का सामना करना पड़ता है। इससे बालों में रूखापन बढ़ने लगता है और हेयर स्ट्रक्चर को प्रभावित करने लगता है ।

कलरिंग के बाद बालों में आने वाले बदलाव एकाएक चिंता का कारण साबित होने लगते हैं। ऐसे में बालों की देखभाल के लिए उचित उपाय करना बेहद आवश्यक है। हेयर कलरिंग के बाद बालों को हेल्दी और मुलायम बनाने के लिए इन टिप्स को करें फॉलो।

इस बारे में डर्माटोलॉजिस्ट डॉ स्वाति मोहन का कहना है कि हेयर कलर में बालों के रंग को हल्का करने के लिए ब्लीच की अधिक मात्रा इस्तेमाल की जाती है। इससे बालों को नमी को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा बालों में टूटने और झड़ने की समस्या भी बढ़ जाती है। वे लोग जो बालों को बार बार रिकलर करते हैं। उससे स्कैल्प का पीएच लेवल असंतुलित होने लगता है। ऐसे में बालों की लैंथ को 8 सप्ताह से पहले दोबारा कलर करने से बचना चाहिए। बालों को हेल्दी रखने के लिए हेयर कलर करवाने से बचें। इससे बालों में मॉइश्चर लॉस की समस्या बढ़ने लगती है और बालों के टैक्सचर को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा बालों की स्मूदनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जेल, स्प्रे और वैक्स के प्रयोग से भी बचना चाहिए।

हेयर कलर कैसे बालों को पहुंचाते हैं नुकसान- बालों पर अप्लाई किए जाने वाले कलर में कैमिकल्स की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इससे बालों में मौजूद सॉफ्टनेस कम होने लगती है और नेचुरल मेलेनिन को प्रभावित करता है। इसके चलते बालों का रंग सफेद हो जाता है। एनआईएच की रिपोर्ट के अनुसार कलरिंग करने से बालों में मौजूद प्रोटीन और लिपिड की मात्रा का स्तर कम होने लगता है। इससे बालों के शाफ्ट के इन्नर और आउटर स्ट्रक्चर में परिवर्तन आने लगता है, जिससे बालों को नुकसान होने लगता है। बालों का टूटना, झड़ना और रूखापन बढ़ने लगता है।

हेयर कलर के बारे में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ चित्रा का कहना है कि हेयर कलर में अमोनिया पाया जाता है, जो बालों की सेहत को नुकसान पहुंचाता है। हेयर कलरिंग के लिए केमिकल्स की मदद से क्यूटिकल्स में कलर को इंसर्ट किया जाता है। इससे बालो की जड़े कमज़ोर होने लगती है और हेयरफॉल की समस्या का सामना करना पड़ता है। बाल बाल डाई लगाने से बालों का पीएच लेवल कम होने लगता है। साथ ही प्राकृतिक मेलेनिन में कमी आती है, जिसके चलते ग्रे हेयर की समस्या बढ़ जाती है।

कलर प्रोटेक्टेंट शैम्पू- बालों को कलर करवाने के बाद साधारण शैम्पू के स्थान पर कलर्ड शैम्पू का ही प्रयोग करें। इससे हेयर कलर जल्दी फेड होने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही बाल मुलायम बने रहते है। दरअसल, कलर प्रोटेक्टेंट शैम्पू का इस्तेमाल करने से बालों में कलर लॉक हो जाता है। इससे साधारण शैम्पू में मौजूद सल्फेट से बालों की रक्षा की जा सकता है और बाल मुलायम बने रहते हैं।

शैम्पू के बाद कंडीशनिंग- बालों की स्मूदनेस को बनाए रखने के लिए कंडीशनिंग करना ज़रूरी है। लीव इंन कंडीशनर या डीप कंडीशनिंग करने से बालों में मॉइश्चर लॉक हो जाता है। इससे बालों का रूखापन कम होने लगता है और बाल हाइड्रेट रहते हैं। सेमी वेट बालों की लेंथ पर लगाकर कुछ देर बाद बालों को धोने से रूखेपन की समस्या का जोखिम कम हो जाता है और बालों का कलर मेंटेन रहता है

प्रोटीन जेल- बालों को कलरिंग से पहले प्रोटीन जेल अवश्य अप्लाई करें। इससे बालों पर केमिकल्स के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इससे फ्रीजी हेयर की संभावना कम होने लगती है। फॉलिकल्स की मज़बूती को बढ़ाने और हेयर पिगमेंट की समस्या को हल करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल बेहद आवश्यक है। किसी भी प्रकार के कलर को अप्लाई करने से पहले प्रोटीन जेल को बालों की रूट्स से लेकर लेन्थ में अवश्य अप्लाई करें।

हेयर ऑयलिंग- बालों के रूखेपन को दूर करने के लिए सप्ताह में 2 बार हेयर ऑयलिंग अवश्य करें। इससे फ्रीजीनेस से बचा जा सकता है और बालों की शाइन मेंटेन रहती है। बालों को ग्लॉसी लुक देने के लिए हेयर ऑयलिंग करें और 30 मिनट के बाद बालों को धो लें। बालों को धोने के लिए क्लोरीनयुक्त पानी का प्रयोग करने से बाल रूखे और कमजोर बनने लगते है। इससे हेयरफॉल का खतरा बना रहता है। स्वीमिंग के दौरान बालों को कवर करें। पूल के पानी में पाई जाने वाली क्लोरीज की मात्रा हेयर डैमेज का कारण साबित होती है।

बालों को बार बार धोने से बचें- सप्ताह में 2 से 3 बार कलर्ड हेयर को धोने से बालों में मौजूद नेचुरल ऑयल धीरे धीरे कम होने लगता है। फॉलिकल्स में मौजूद प्रोटेक्टिव ऑयल बालों की जड़ों को मज़बूत बनाता है। इसके अलावा बालों को धोने के लिए कलर प्रोटेक्टेंट सल्फर फ्री शैम्पू का प्रयोग करें।

हेयर स्टाइनिंग टूल्स इस्तेमाल न करें- बालों की नमी को बरकरार रखने के लिए बालों का सुखाने से लेकर उन्हें अलग लुक देने के लिए हेयर स्टाइनिंग टूल्स से बचें। इससे बालों का टूटना, झड़ना और स्प्लिट एंड्स की समस्या से बचा जा सकता है। बालों को सीधा करने के लिए की जाने वाली प्रेसिंग बालों को हीट से डैमेज करती है। इससे कलरिंग पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। बालों को यूवी रेज़ के प्रभाव से बचाने के लिए ढ़ककर रखें। धूप में निकलने से पहले हैट या स्कार्फ से बालों को ढ़कें। इससे बालों का रंग लंबे वक्त तक बना रहता है। इसके अलावा बालों में बढ़ने वाले

अवश्य इसके

सुबह अचानक गिरे ब्लड शुगर लेवल को यूं पहचाने, जानिए सबसे पहले क्या करें?

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसे आपको मैनेज करना चाहिए। दरअसल, वैसे तो डायबिटीज के मरीज शुगर लेवल बढ़ने पर दवाई लेते हैं। लेकिन कई बार शुगर लेवल लो भी हो सकती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाई ब्लड शुगर लेवल की तुलना लो ब्लड शुगर का लेवल सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अक्सर पेशेंट को ये समस्या सुबह हो सकती है। यहां बता रहे हैं लो ब्लड शुगर होने पर शरीर में क्या बदलाव दिखते हैं और इससे निपटने के लिए सबसे पहले क्या करें।

बढ़ी हुई हार्ट बीट शुगर लेवल कम होने का संकेत हो सकती है। दरअसल, यह ब्लड को ज्यादा तेजी से पंप करके ग्लूकोज की कमी की भरपाई करने की कोशिश करता है।

लो ब्लड शुगर होने पर शरीर की तनाव प्रतिक्रिया के कारण कंपकंपी हो सकती है।

ज्यादा पसीना आना लो ब्लड ग्लूकोज का लक्षण हो सकता है।

लो ब्लड शुगर शरीर की तनाव प्रतिक्रिया के कारण घबराहट या चिंता की भावना पैदा कर सकता है।

लो ब्लड शुगर के कारण रक्त वाहिकाओं और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ने की वजह से सिरदर्द हो सकता है।

अगर सुबह के समय आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है तो 15-15 नियम को फॉलो करें। इसे अपनाने के लिए 15 ग्राम तेजी से काम करने वाले कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज की गोलियां, बिस्कुट, फलों का रस या नींबी पानी पीएं और फिर 15 मिनट तक इंतजार करें। फिर ब्लड शुगर के लेवल की दोबारा जांच करें। अगर स्तर फिर भी कम रहता है तो इस प्रतिक्रिया को ब्लड शुगर स्थिर होने तक दोहराएं।

डायबिटीज में बेस्ट माने जाते हैं ये फूड, एक्सपर्ट ने खुद दी खाने की सलाह

डायबिटीज की समस्या से इन दिनों ज्यादातर लोग पीड़ित हो रहे हैं। हालांकु, इससे बचने के लिए बहुत से लोग मीठे से परहेज करते हैं लेकिन क्या डायबिटीज को कंट्रोल में रखने और इससे होने वाली समस्याओं से बचने के लिए ये काफी है? नहीं क्योंकि कुछ खाने की चीजें मीठी न होने के बावजूद भी नैचुरली मिठी होती हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर दीक्षा भावसार के लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने बताया है कि डायबिटीज की समस्याओं को रोकने के लिए किन चीजों को खा सकते हैं-

- आंवले में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है और यह आपको थकान से बचाने में मदद करता है। इसे फल, पाउडर या जूस के रूप में ले सकते हैं।
- चना पचाने में सबसे अच्छा और आसान प्रोटीन है, जो आपको ऊर्जा देता है। ब्लड शुगर को कम करता है और अनावश्यक खाने की लालसा को रोकने में भी मदद करता है।
- अपराजिता फूल की चाय कोर्टिसोल को कम करने और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है।
- पपीते में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन और विटामिन सी, ई और ए होता है। यह शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है।
- बेल फल और पत्तियां- दोनों आपके मेटाबॉलिज्म में सुधार करने और आपके शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखने का काम करती हैं।
- मोरिंगा एक सुपर फूड है जो इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने, वजन घटाने में मदद करता है। इसे आपके खाने में शामिल किया जा सकता है। रोजाना 1 चम्मच पाउडर रूटीन में शामिल करें।

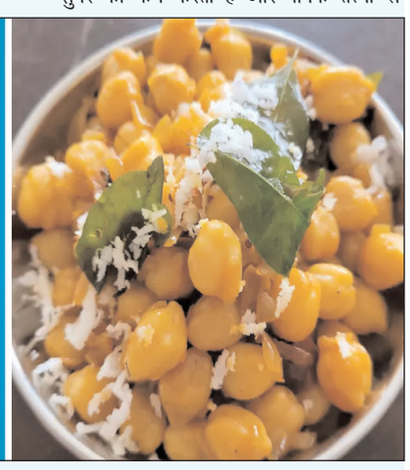

- मेथी शुगर लेवल को संतुलित करने में मदद करती है और इसे रात भर पानी में भिगोकर रखा जा सकता है और अगली सुबह खाली पेट इसे खाया जा सकता है।
- डायबिटीज पेशेंट नाश्ते में नारियल खा सकते हैं।
- डायबिटीज में जामुन खा सकते हैं, यह आपके ब्लड शुगर के लेवल को मैनेज करने और आपकी लालसा को दूर रखने में भी अच्छा काम करता है।
- इंडियन खाने में हल्दी का खूब इस्तेमाल किया जाता है, इसे हर सब्जी में डाला जा सकता है। डायबिटीज की समस्याओं से बचने के लिए इसे आंवले के साथ मिलाकर खाएं।
- डायबिटीज पेशेंट के लिए रागी का एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यह ग्लूटेन-फ्री है, ये ब्लड शुगर को कम करता है और पोषक तत्वों से भरपूर होता है।
- अनार डायबिटीज और मीठा खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छा है।
- अलसी के बीजों को भोजन के बाद मुखवास के रूप में खाया जा सकता है। यह इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है। साथ ही ये डायबिटीज पेशेंट के लिए दिल संबंधी समस्याओं को भी रोकता है।
- सोंठ पाउडर को हर्बल चाय में मिलाकर खाएं, ये भी डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छा है।
- दालचीनी को हर्बल चाय और खाने में मिलाया जा सकता है। हाई शुगर लेवल को संतुलित करने में ये फायदेमंद होती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का गठबंधन है इंडियाः नित्यानंद

पटना। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। पक्ष-विपक्ष के बीच सत्ता की लड़ाई धीरे-धीरे घमासान रूप लेती जा रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत सत्ताधारी एनडीए के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रही विपक्षी गठबंधन इंडिया पर बेहद तीखा हमला करते हुए उसे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा करार दिया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, विपक्ष गठबंधन इंडिया भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों और गरीबों का हक हड़पने वालों का गठबंधन है और यह भाई-भतीजावाद के साथ तुष्टिकरण की नीति में विश्वास करता है। भाजपा नेता राय ने कहा, विपक्षी गठबंधन इंडिया में सत्ता के लिए जितना संघर्ष हो रहा है, इससे साफ पता चलता है कि उनके पास कोई नीति नहीं है। उन्हें न तो लोगों और उनके के लिए किये जा रहे विकास की परवाह नहीं है। इंडिया गठबंधन की हालत देखते हुए साफ लग रहा है कि जहां स्वार्थ होगा, वहां संघर्ष होगा।

कांग्रेस जमीनी हकीकत से कट चुकी है : मुकुल संगमा

नयी दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ सीट-बंटवारे के समझौते के लिए ''काफी'' इंतजार किया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 'इंडिया' गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस जमीनी हकीकत से कट चुकी है। टीएमसी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की, जिसमें कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट काद दिया गया और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और कीर्ति आजाद जैसे कई नए चेहरों को शामिल किया गया। टीएमसी की घोषणा के बाद 'एक्स' पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने बार-बार ''पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ सम्मानजनक सीट-बंटवारे समझौते'' की अपनी इच्छा व्यक्त की है। टीएमसी द्वारा जारी एक वीडियो बयान में संगमा ने कहा, ''हमने काफी समय तक इंतजार किया, पूरा देश देख सकता है।

अयोग्य छह विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 'अयोग्य' ठहराने के फैसले के खिलाफ दायर छह बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुनवाई करने वाला है। इन विधायकों ने हिमाचल प्रदेश में हाल के राज्यसभा चुनाव में 'क्रॉस वोटिंग' करते हुए भाजपा के उम्मीदवार को वोट दिया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पार्टी व्हिप की 'अवहेलना' करने के लिए कांग्रेस की याचिका पर छह विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। पार्टी व्हिप के मुताबिक उन्हें सदन में उपस्थित रहने और बजट के लिए मतदान करने की आवश्यकता थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ विधानसभा अध्यक्ष के 29 फरवरी के फैसले के खिलाफ याचिका पर 12 मार्च को सुनवाई करेगी।

आप ने लोकसभा अभियान की कर दी शुरुआत

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत ने मोहाली में 13-0, पंजाब जीतेगा का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब का मान बढ़ाने के लिए इसे 13-0 करें। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। इस बारे में आप ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि पंजाब की जनता पंजाब में हो रहे सुधार और बदलाव की साक्षी बन रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में भी पंजाब आम आदमी पार्टी के साथ है। आज से लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान लोगों को पंजाब के लिए उन्हें 13-0 से जिताने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंजाब में आप सरकार गिराने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन सीएम भगवंत मान अकेले लड़ रहे हैं। अगर उन्हें जिता देंगे तो सीएम भगवंत मान के लिए 13 सीटें 13 हाथ होंगे।

संविधान में संशोधनः हेगड़े की टिप्पणी उनके निजी विचार

बेंगलुरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को संविधान में संशोधन पर पार्टी सांसद अनंत कुमार हेगड़े की टिप्पणी से उपजे विवाद को खत्म करने की कोशिश करते हुए इसे उनका ''व्यक्तिगत विचार'' बताया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। कर्नाटक के सांसद की टिप्पणी को लेकर विपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधने के बीच पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भाजपा ने हमेशा संवैधानिक लोकाचार और राष्ट्रीय हित के अनुरूप काम किया है। भाजपा की कर्नाटक इकाई ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''संविधान पर सांसद अनंत कुमार हेगड़े की टिप्पणी उनके निजी विचार हैं और पार्टी के रुख को प्रतिबिंबित नहीं करती है। भाजपा देश के संविधान को बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराती है और हेगड़े से उनकी टिप्पणी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगेगी।''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम में कहा

जब भी मैंने महिला सशक्तिकरण की बात की कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा अपमान किया

नई दिल्ली। राजधानी में हुए नारी- विकसित भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी की महिला लाभार्थियों से बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम में नमो ड्रोन दीदियों के बीच ड्रोन वितरित किए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज मुझे नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1,000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सौंपने का अवसर मिला। देश में 1 करोड़ से ज्यादा बहने लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह और नित्यानंद राय भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज 10,000 करोड़ रुपए की राशि इन दीदीयों के खाते में जमा कराई गई हैं। कोई भी देश या समाज में नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों के लिए महिलाओं की मुश्किलें और उनका जीवन कभी प्राथमिकता नहीं रही, मेरा अनुभव है कि अगर महिलाओं का थोड़ा अवसर-सहारा मिल जाए, तो उन्हें सहारे की जरूरत नहीं रहती है वे लोगों का सहारा बन जाती हैं। कार्यक्रम के मुख्य केंद्र में नमो ड्रोन दीदी द्वारा पूरे भारत में कृषि ड्रोन का प्रदर्शन होगा। 1,000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपे गए। सेल्फ हेल्प ग्रूप को बैंक ऋण के रूप में या पूंजीकरण सहायता निधि के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

दिल्ली में सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, जब भी मैंने महिला सशक्तिकरण की बात की है, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरा अपमान किया। मोदी की योजनाएं जमीनी अनुभवों का नतीजा हैं।

दिल्ली में सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, मैं देश की हर महिलाओं को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति

के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा।

गुरुग्राम से कई राज्यों के लिए 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देशभर में करीब 1 लाख करोड़ रुपये की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले पीएम मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे के मॉडल का निरीक्षण किया। इस बीच, प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर निर्माण श्रमिकों से भी बातचीत की। एनएच-48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने और भीड़भाड़ को कम करने में मदद करने के लिए, प्रधान मंत्री मोदी ने ऐतिहासिक द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का भी उद्घाटन किया।

8-लेन द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा खंड लगभग 4,100 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और इसमें 10.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली-हरियाणा सीमा से बसई रेल-ओवर-ब्रिज (आरओबी) और 8.7 के दो पैकेज शामिल हैं। किलोमीटर लंबा बसई आरओबी से खेड़की दौला तक। यह दिल्ली में आईजीआई हवाई अड्डे और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई अन्य प्रमुख परियोजनाओं में 9.6 किमी लंबी छह-लेन शहरी विस्तार रोड-द्वितीय (यूईआर-द्वितीय) - पैकेज 3 नांगलोई - नजफगढ़ रोड से दिल्ली में सेक्टर 24 द्वारका खंड तक शामिल है; लगभग रु. की लागत से लखनऊ रिंग रोड के तीन पैकेज विकसित किये गये। उत्तर प्रदेश में 4,600 करोड़, आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 2,950 करोड़ रुपये की लागत से ह॥16 का आनंदपुरम पेंडुरथी-अनाकापल्ली खंड विकसित किया गया, ह॥-21 का किरतपुर से नेरचौक खंड (2 पैकेज) जिसकी कीमत लगभग रु हिमाचल प्रदेश में 3,400 करोड़; डोबास्पेट - हेसकोटे खंड (दो पैकेज) की कीमत रु. कर्नाटक में 2,750 करोड़ रुपये के अलावा देशभर के अलग-अलग राज्यों में 20,500 करोड़ रु 42 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी ने 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में जिस तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कार्य चल रहा है, उतनी ही तेजी से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। देश में हो रहे लाखों करोड़ रुपये के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत सिर्फ कांग्रेस और उसके अहंकारी गठबंधन को हो रही है। उन्हें नींद नहीं आ रही है। इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि मोदी चुनाव के कारण लाखों करोड़ रुपये का काम कर रहे हैं। 10 साल में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों के विचार नहीं बदले। उनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है- सब नकारात्मक। देश में तेजी से हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम, भारत को उतनी ही तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बनाएगा। मैं न छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं और न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो चाहिए... विराट चाहिए, विशाल चाहिए और तेज गति से चाहिए क्योंकि 2047 में मुझे देश को %विकसित भारत% के रूप में देखना है।

सरकार को डर है कि चुनावी बॉण्ड पर उसके सारे राज खुल जायेंगे: कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने चुनावी बॉण्ड का विवरण देने के लिए समय बढ़ाने की भारतीय स्टेट बैंक की मांग को हास्यास्पद करार देते हुए सोमवार को दावा किया कि सरकार को इस बात का डर है कि उसके सारे राज खुल जाएंगे। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय एक बार फिर से भारतीय लोकतंत्र को सरकार की साजिशों से बचाने के लिए सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामला बड़े भ्रष्टाचार का है तथा यह सरकार एवं उसके कॉरपोरेट मित्रों के बीच की सांठगांठ को भी उजागर करता है।

उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बॉण्ड संबंधी जानकारी का खुलासा करने के लिए समयसीमा बढ़ाए जाने का अनुरोध करने वाली भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की याचिका सोमवार को खारिज कर दी और उसे 12 मार्च को कामकाजी घंटे समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड संबंधी विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया। पीठ ने एसबीआई से पूछा कि उसने चुनावी बॉण्ड योजना को पिछले महीने रद्द किए जाने से पहले राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए बॉण्ड संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं।

वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया, उच्चतम न्यायालय एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र को इस शासन की कुटिल साजिशों से बचाने के लिए आगे आया है। उन्होंने दावा किया, एसबीआई द्वारा एक दिन के साधारण से काम के लिए समय बढ़ाने की मांग करना हास्यास्पद था। सच तो यह है कि सरकार को डर है कि उनके सारे राज़ सामने आ जायेंगे। वेणुगोपाल का कहना था, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रमाणित यह महाभ्रष्टाचार का मामला, भाजपा और उसके भ्रष्ट कॉरपोरेट मित्रों के बीच अपवित्र सांठगांठ को उजागर करेगा। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, जो सत्ता में आए थे स्विस बैंकों के खातों को सार्वजनिक करने की बातें करके वो आज एसबीआई तक के आंकड़ों को सार्वजनिक करने में थर-थर कांप रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने को कहा है। याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और एसबीआई को कल तक सभी दस्तावेज जमा करने के कड़े निर्देश दिए। यह बहुत अच्छा फैसला है, मैं इसका स्वागत करती हूं। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसबीआई को 12 मार्च, 2024 को व्यावसायिक घंटों के अंत तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है। ईसी जानकारी संकलित करेगा और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च, 2024 शाम ??5 बजे तक विवरण प्रकाशित करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 6 मार्च तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड खरीद के सभी विवरण प्रस्तुत करने और प्रक्रिया में देरी करने के अपने पिछले आदेश का पालन नहीं करने और प्रक्रिया में देरी करने के लिए एसबीआई को अवज्ञा के लिए भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि यदि एसबीआई इस आदेश में बताई गई समयसीमा के अनुसार निर्देशों का पालन नहीं करता है तो यह अदालत जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

खेल
प्रमुख समाचार

रोहित शर्मा चेन्नई सुपरकिंग्स की कप्तानी कर सकते हैं

नईदिल्ली। आईपीएल 2024 से पहले ही मुंबई इंडियंस ने ऑल कैश डील करते हुए गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पंड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी करा दी थी। हार्दिक पंड्या ने अपना आईपीएल करियर मुंबई इंडियंस के साथ ही शुरू किया था और रोहित शर्मा की कप्तानी में अपना नाम बनाया था। वहीं मुंबई इंडियंस ने रोहित की जगह हार्दिक को कप्तान बना दिया था। वहीं अब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेल चुके अंबाती रायुडू ने रोहित को लेकर कुछ बातें कही हैं। न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर अंबाती ने कहा कि, रोहित शर्मा अभी कम से कम 5-6 साल और आईपीएल में खेल सकते हैं। अगर रोहित कप्तानी करना चाहते हैं तो, पूरी दुनिया उनके लिए खुली हुई है। वह जिस भी टीम के लिए चाहें कप्तानी कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से खेलें, अगर धोनी संन्यास लेते हैं तो ऐसे में रोहित शर्मा सीएसके की कप्तानी कर सकते हैं। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की कप्तानी में पांच खिताब जीते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स ने एमएस धोनी की कप्तानी में पांच आईपीएल खिताब जीते हैं। रोहित और धोनी दोनों ही आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। दोनों की ही टीमें आईपीएल इतिहास की सबसे सफल फ्रेंचाइजी टीमें हैं। रायुडू के अनुसार रोहित चेन्नई सुपरकिंग्स के कल्चर में एकदम फिट बैठेंगे।

आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर आएंगे ऋषभ पंत

ऋषभ पंत के फैंस के लिए खुशखबरी है। दरअसल, एक रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ पंत को इस साल के आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने के लिए बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी से फिटनेस मंजूरी मिल गई है। अब इसी के साथ पंत आईपीएल में खेलने के लिए तैयार हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी 22,400 के नीचे

नईदिल्ली। देसी शेयर बाजार में जारी तेजी पर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार (11 मार्च) को ब्रेक लग गया। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर रुझानों के बीच रिलायंस, टाटा मोटर्स, धातु और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली के कारण शेयर बाजार 600 से ज्यादा अंक की भारी गिरावट लेकर बंद हुआ। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 617 अंक कमजोर हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 161 अंक की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 616.75 अंक यानी 0.83 फीसदी की भारी गिरावट के साथ 73,502.64 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 73,433.91 और 74,187.35 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (ह्स्श्व) के निफ्टी में भी 160.90 अंक यानी 0.72 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 22,332.65 अंक पर बंद हुआ।

चीनी स्मार्टफोन कंपनियां भारत में घुटनों के बल!

नईदिल्ली। पिछले कुछ सालों में, भारत में लगभग सभी प्रमुख चीनी स्मार्टफोन कंपनियों पर गहरी जांच का दबाव रहा है। इन कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग, सीमा शुल्क और आयकर चोरी जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, वीवो और ओप्पो अब सरकार के साथ लंबे समय से चले आ रहे टकराव के मुद्दे को सुलझाने में मदद के लिए प्रोडक्ट सप्लाई के प्राइमरी सोर्स के रूप में हर राज्य में भारतीय वितरकों को नियुक्त कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में, भारत में चीनी स्मार्टफोन कंपनियों की बढ़ती शक्ति और प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इन कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग, सीमा शुल्क चोरी और आयकर चोरी जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के परिणामस्वरूप, सरकार ने इन कंपनियों पर छापेमारी की है और उनके बैंक खातों को सील कर दिया है।

कोल्ड ड्रिंक और एसी की बिक्री 40 फीसदी बढ़ने की उम्मीद

नईदिल्ली। ठंडे पेय पदार्थों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के निर्माताओं को उम्मीद है कि 2023 की तुलना में इस साल तापमान अधिक होने की उम्मीद से इस गर्मी में मांग ज्यादा होगी। पिछले साल असामयिक बारिश के कारण तापमान कम रहा और बिक्री में कमी आई। एफएमसीजी विनिर्माताओं को उम्मीद है कि इस साल बिक्री 15-40 प्रतिशत अधिक रहेगी। इसके अतिरिक्त रमजान और लोक सभा चुनाव की वजह से भी एफएमसीजी कंपनियों को खपत बढ़ने की उम्मीद है। आईटीसी के मुख्य परिचालन अधिकारी, डेयरी और पेय पदार्थ, संजय सिंघल ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, हम मांग से निपटने के लिए तैयार हैं और पिछले एक साल में हमने कई प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इनमें नारियल पानी और फलों के जूस शामिल हैं। रसना के निर्माता को उम्मीद है कि मांग पिछले साल की तुलना में 15-20 प्रतिशत अधिक रहेगी।

चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को झटका

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 से राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अनुरोध को खारिज कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया, जिसमें बैंक को 12 मार्च तक विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया गया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक बैंक द्वारा शेयर किए गए डिटेल को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करने का भी निर्देश दिया।

बौद्धिक नवाचार आधारित व्यवस्था की ओर, पर ऊंचे लक्ष्यों के लिए कुछ करना बाकी

जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में अमेरिकी उद्योग मंडल 'यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स' के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में वैश्विक बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक 2024 में भारत दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भी भारत इसी क्रम पर स्थित था। आईपी सूचकांक के तहत शीर्ष क्रम पर जिन 10 देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें क्रमशः अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, जापान, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्पेन तथा स्विट्जरलैंड हैं। बौद्धिक संपदा में आविष्कार, रचनात्मक व कलात्मक कार्य, डिजाइन, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और शोध व नवाचार शामिल हैं।

हालांकि इस नई आईपी रिपोर्ट में भारत की बौद्धिक संपदा आधारित नवाचार गतिविधियों की प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि भारत बौद्धिक नवाचार के जरिये अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने की संभावनाओं वाला देश है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आईपी मापदंडों के मद्देनजर भारत का आकार और आर्थिक रसूख वैश्विक पटल पर बढ़ रहा है। यदि हम बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े अन्य वैश्विक संगठनों की रिपोर्टों को देखें, तो पाते हैं कि भारत इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब भी देश के तेज विकास के ऊंचे लक्ष्यों के लिए बौद्धिक संपदा शोध और नवाचार में भारत को काफी कुछ करना जरूरी है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2023 की रैंकिंग में 132 अर्थव्यवस्थाओं में भी भारत 40वें पायदान पर दिखाई दे रहा है। खास बात यह भी है कि

इस सूचकांक में भारत 37 निम्न-मध्यम-आय समूह वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच अग्रणी बनकर उभरा है।

साथ ही, भारत नवाचार के संबंध में मध्य और दक्षिणी एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊपर है। बौद्धिक संपदा शोध एवं नवाचार की दुनिया में भारत की रैंकिंग यह दर्शा रही है कि भारत इनोवेशन का हब बनता जा रहा है। भारत में शोध एवं नवाचार को बढ़ाने में डिजिटल ढांचे और डिजिटल सुविधाओं की भी अहम भूमिका है। भारत आइटी सेवा निर्यात और वेंचर कैपिटल हासिल करने के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत के नवाचार दुनिया में सबसे प्रतियोगी, किफायती, टिकाऊ, सुरक्षित और बड़े स्तर पर लागू होने वाले समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भारत में करीब 1.25 लाख स्टार्ट-अप हैं, जिनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।

गौरतलब है कि बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार के आधार पर ही विभिन्न देशों के उद्यमी और कारोबारी किसी देश में अपने उद्योग-कारोबार शुरू करने संबंधी निर्णय लेते हैं। हालांकि भारत के विकास में बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े तीन आधारों की बढ़ती भूमिका दिखाई दे रही है, लेकिन इन आधारों से विकास को ऊंचाई देने के लिए इस क्षेत्र में सरकार व निजी क्षेत्र को परिव्यय बढ़ाना होगा। इस समय भारत में आर ऐंड डी पर जीडीपी का करीब 0.67 प्रतिशत ही व्यय हो रहा है। भारत में शोध एवं नवाचार पर खर्च वैश्विक औसत 1.8 फीसदी से भी कम है। फिलहाल देश में निजी क्षेत्र का आर ऐंड डी पर खर्च जीडीपी का करीब 0.35 फीसदी है।

इसमें कोई दोमत नहीं है कि सरकार बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार की अहमियत को समझते हुए इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए दिखाई दे रही है। वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में वित्तमंत्री सीतारमण ने उभरते क्षेत्रों में नवाचार और शोध को प्रोत्साहन देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष की स्थापना करने की घोषणा की है। उम्मीद है कि सरकार अमेरिकी उद्योग मंडल, यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट, 2024 के तहत भारत सरकार बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार के वर्तमान ढांचे में मौजूद खामियों को दूर करने और भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक नया मॉडल बनाने की डगर पर आगे बढ़ेगी।

मोदी की एक और गारंटी होने जा रही पूरी

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

कृषक उन्नति योजना

दिनांक 12 मार्च 2024

प्रदेश के 24.72 लाख से अधिक किसानों के खाते में आएंगे

₹13,320 करोड़

खुशहाल किसान ■ समृद्ध छत्तीसगढ़ ■ विकसित भारत

- एमएसपी के बाद अब अंतर की राशि का भुगतान करने जा रही सरकार
- किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए के मान से आदान सहायता

संवाद- 39984/118

मोदी की गारंटी - विष्णु का सुशासन

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.